

एक सामाजिक प्रयोग
को
समेटने पर

संक्षिप्त रपट

किशोर भारती

पो.बाक्स नं. 7, पिपरिया
जिला - होशंगाबाद
मध्यप्रदेश 461775

नवंबर 1991

प्रकाशन: नवंबर 1991

प्रकाशक: सचिव, कार्यकारिणी समिति
किशोर भारती
पो.बाक्स नं. 7, पिपरिया
जिला - होशंगाबाद
मध्यप्रदेश 461 775

मुद्रक : मॉडर्न प्रेस.
महात्मा गांधी रोड
रायपुर - 492001

एक सामाजिक प्रयोग को समेटने पर

संक्षिप्त रपट

आपको शायद पता चल ही गया होगा कि विगत 3 - 4 वर्षों से होशंगाबाद जिले (म.प्र.) के पूर्वी छोर पर सन् 1972 से कार्यरत किशोर भारती संस्था में उसके समस्त कार्यक्रमों को बंद करने एवं उसके परिसर को राज्य शासन को लौटा देने की प्रक्रिया चल रही थी। आपको हम यह रपट इस प्रक्रिया को अपने निर्णायक बिंदु पर पहुंचा देने के बाद भेज रहे हैं। इस वर्ष 30 जनवरी को किशोर भारती कार्यकारिणी समिति द्वारा राज्य शासन को पूर्व में दिये गये लिखित आवेदनों पर कार्यवाही करते हुये कलेक्टर, होशंगाबाद ने संस्था के ग्राम पलिया पिपरिया में स्थित 148.29 एकड़ भूमि में फैले परिसर की समस्त अचल संपत्ती का विधिवत कब्जा ले लिया। इसी तारतम्य में अप्रैल 1991 में कलेक्टर ने सन् 1972 में किशोर भारती को शासकीय पट्टे पर दी गई उक्त भूमि का पट्टा भी निरस्त करके परिसर की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी तहसीलदार, बनखेड़ी को सौंप दी। पिछले वर्ष 31 मार्च को पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार संस्था ने अपने समस्त कार्यक्रम बंद कर दिये थे। उसी समय संस्था में कार्यरत लगभग 20 कार्यकर्ताओं को वैकल्पिक ज़ीविका की व्यवस्था करने के लिये उनके सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के पीछे एक माह का वेतन एवं तीन माह का अतिरिक्त वेतन अनुग्रह राशि स्वरूप दिया गया।

किशोर भारती संस्था ने राज्य शासन को सौंपी गई अचल संपत्ति का विधिवत मूल्यांकन करवाके शासन से उसका न्यायोचित मुआवजा मांगा है। अनेक स्मरण पत्रों एवं संबंधित अधिकारियों से कई बार भेंट के बावजूद इस मसले पर शासन का उत्तर हमें आज तक नहीं मिला है।

निर्णय की पृष्ठभूमि

निःसंदेह किशोर भारती कार्यकारिणी समिति द्वारा इस संबंध में फरवरी 1989 में लिये गये औपचारिक निर्णय को क्रियान्वित करने का काम न तो इतना सरल था और न ही सुखद। कई ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजर कर और विरोध-प्रतिरोध की अनेक खाइयों को पार करके ही यह निर्णय क्रियान्वित हो

सका है। वैसे तो किशोर भारती को समेट देने की बात सन् 1978-79 में ही शुरू हो गयी थी। परंतु हर बार हममें से ही कोई-न-कोई व्यक्ति, कुछ-न-कुछ नया तर्क देकर किशोर भारती के अस्तित्व को मध्यप्रदेश में सामाजिक परिवर्तन के लिये आवश्यक सिद्ध कर देता था और हमारे कार्यक्रमों की गाड़ी एक बार फिर से नये जोश के साथ आगे बढ़ जाती थी। संस्था का काम समेटने का यह प्रस्ताव बार - बार क्यों उठता रहा और हर बार निर्णय का रूप लेने के पहले ही क्यों वापिस ले लिया जाता था, इस बात को हम किसी भावी परचे का विषय जरूर बनायेंगे।

यहां इतना कहना ही यथेष्ट है कि जून 1987 की बैठक में इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय लेने के इरादे से कार्यकारिणी समिति ने तत्कालीन कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व में जुड़े हुये कई अन्य साथियों को भी आमंत्रित किया था। इस व्यापक भागीदारी में एक लंबी बहस व अनेक मतभेदों के बाद यह बैठक संस्था की समस्त गतिविधियों को बंद कर देने एवं परिसर की भूमि शासन को लौटा देने के निर्णय पर पहुंच तो पायी, हालांकि विभिन्न साथियों ने इसके अलग-अलग आधार प्रस्तुत किये। ये आधार सारांश में इस प्रकार हैं-

1. किशोर भारती शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी। नाना प्रकार के प्रयोगों के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से नहीं, वरन् राजनैतिक आंदोलनों व संगठनों के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका कुछ नये रास्ते खोजने और उत्प्रेरक की अवश्य हो सकती है, परंतु निर्धारक की नहीं। प्रगतिशील राजनैतिक आंदोलनों व संगठनों के अभाव में स्वैच्छिक संस्थाओं की इस सहयोगी भूमिका का दायरा इतना सिमट जाता है कि उनमें लगने वाली भारी-भरकम ऊर्जा और साधनों की सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
2. सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से शिक्षा और आर्थिक विकास के जो भी प्रयोग कार्यकर्ता समूह करना चाहता था या कर सकता था, वे पहले 14 सालों में (1986 - 87 तक) किये जा चुके थे। उसके बाद कार्यक्रम या प्रकल्प केवल इसलिये उठाये जा रहे थे चूंकि उनका उठाना संस्था और कार्यकर्ताओं के अपने अस्तित्व को बनाये भर रखने के लिये जरूरी हो गया था।
3. पिछले कुछ वर्षों से कार्यक्रमों में दिशाहीनता झलक रही थी और समूह में ऐसा नेतृत्व नहीं था जो इस भ्रम की स्थिति को दूर करके स्पष्ट

दिशा दे सके।

4. नेतृत्व की कमजोरी एवं दिशाहीनता के कारण संस्था की स्थिति लुढ़कती-सी हो गई थी, हालांकि हममें से कई लोगों को यह स्वीकारने में बहुत मनोवैज्ञानिक दिक्रत आई। इसका साफ असर लोगों की कार्यकुशलता एवं स्वप्रेरणा पर दिखने लगा था। इसके कारण कार्यकर्ताओं के आपसी संबंधों को लेकर भी नाना प्रकार की उलझनें पैदा हो गई थीं और निरर्थक विवाद उभरने लगे थे।
5. कार्यक्रमों की कसौटी उनके सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति न होकर, क्रियाओं को मात्र चलाते रहना ही हो गयी थी।

बेशक, ऊपरोक्त अवलोकनों एवं तर्कों से जून 1987 की बैठक के सभी सहभागी सहमत नहीं थे। एक अल्पमत भी था (जो फरवरी 1989 के औपचारिक निर्णय तक कायम रहा) जिसके अनुसार किशोर भारती जैसी संस्थाओं का बने रहना ही सामाजिक परिवर्तन के लिये आवश्यक लग रहा था। ऊपरोक्त पांचों आधारों को लेकर समस्त गतिविधियां बंद करने व परिसर लौटाने का निर्णय सैद्धांतिक तौर पर लिया तो गया पर उसका क्रियान्वयन तीन वर्षों के लिये स्थगित कर दिया गया। ऐसा इसलिये करना पड़ा चूंकि कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी पहल पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) को तीन नये प्रकल्प अनुदान हेतु भेज दिये थे और वे उनको क्रियान्वित करने के लिये उत्सुक थे। कार्यकारिणी समिति ने अपनी परंपरानुसार कार्यकर्ताओं की इस इच्छा का आदर करते हुये परिसर समेटने के अपने निर्णय को तीन साल तक स्थगित रखने की घोषणा की।

अगले दो वर्षों (1987-89) के दरम्यान भी उक्त निर्णय को बदलकर संस्था के तत्वावधान में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय (राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार) या एक स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव भी सामने आये। परंतु नेतृत्व अभाव, क्रियान्वयन का बीड़ा उठाने की तैयारी में कमी एवं विचारों की अस्पष्टता के कारण इन पर अमल करना संभव नहीं हो सका। सन् 1988 खत्म होते-होते एक ऐसी स्थिति भी बनी जब किशोर भारती का कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता संस्था के संचालन या कार्यक्रमों को दिशा देने की भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार न था। अतः फरवरी 1989 की बैठक में कार्यकारिणी समिति ने अपने दो वर्ष पुराने निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये हरी झंडी दे दी।* इसके बाद भी परिसर में ग्रामीण विश्वविद्यालय या स्कूल स्थापित

* इसके बावजूद यह स्पष्ट समझ थी कि परिसर समेटने की प्रक्रिया के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा स्वीकृत तीनों शैक्षिक प्रकल्पों को पूरा करने की जिम्मेदारी संस्था निभायेगी।

करने के प्रयास विभिन्न समूहों के द्वारा चालू रहे, परंतु कार्यकारिणी समिति द्वारा बार-बार दिये गये प्रोत्साहन एवं अवसरों के बावजूद वे ठोस रूप न ले सके।

सामग्री का वितरण

किशोर भारती संस्था ने अपने अट्ठारह वर्षों के कार्यकाल में जो संसाधन और चल संपत्ति जुटाई थी उसका क्या किया गया, इसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार है -

- परिसर में स्थित पुस्तकालय (फर्नीचर सहित), अक्टूबर 1990 में मध्यप्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल को सौंप दिया गया।
- परिसर में स्थित दस्तावेज केन्द्र, अक्टूबर 1990 में मध्यप्रदेश शासन की प्रशासन अकादमी, भोपाल को सौंपा गया।*
- शहीद भगतसिंह पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र, पिपरिया, अगस्त 1990 में पिपरिया की नवचेतना समिति को सौंपा गया जो पिपरिया में एक अच्छा हाईस्कूल चला रही है।
- बाल संदर्भ पुस्तकालय, जून 1991 में दो वर्ष के लिये मध्यप्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल को सौंपा गया। बच्चों के लिये कार्यशालायें करने व बाल साहित्य की रचना हेतु इसका उपयोग किया जायेगा।
- शेष पुस्तकें निम्नांकित संस्थाओं व स्कूलों को दी गई -
 - बनखेड़ी विकासखंड (जिला होशंगाबाद) के दो हाईस्कूल (शा.उ.मा.शाला, बनखेड़ी व चांदौन);
 - पिपरिया शहर का एक प्रायवेट स्कूल (ज्ञानोदय सोसायटी का महेश कान्वेंट स्कूल);
 - रूपांतर (रायपुर, म.प्र.) - 'दिशा' ट्रस्ट (दिल्ली) का औपचारिकतर शिक्षा केन्द्र;
 - श्री सार्वजनिक पुस्तकालय, गाडरवाड़ा (जिला नरसिंहपुर, म.प्र.), एवं
 - एकलव्य, भोपाल को उनके पिपरिया फील्ड सेंटर हेतु।

* हाल में दस्तावेज केन्द्र को प्रशासन अकादमी से नेशनल सेंटर फॉर ड्यून सेटलमेंट्स एंड इन्वायरनमेंट, भोपाल को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

- शिक्षण साधन, अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित चयनित शिक्षा साहित्य व बाल गतिविधियों से संबंधित अन्य सामग्री, एकलव्य, भोपाल को उनके पिपरिया फील्ड सेंटर हेतु दी गई।
- जीप (4-व्हील ड्राइव, 1988 मॉडल), निर्माण (नई दिल्ली) को नर्मदा बचाओ आंदोलन के उपयोग हेतु दी गई।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) से प्राप्त अनुदान में से खरीदी गई पूंजीगत सामग्री का वितरण इस प्रकार किया गया-
 - मध्यप्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल;
 - गांधी भवन, भोपाल ;
 - सेवा, भोपाल;
 - अर्धशासकीय संस्था नर्मदा निर्मिती, होशंगाबाद ;
 - नवचेतना समिति, पिपरिया; और
 - बनखेड़ी एवं पिपरिया क्षेत्र के कुछ शासकीय व निजी स्कूल।

(उक्त वितरण को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।)
- किशोर भारती ने अपने स्रोतों (दान एवं विविध आय) से जुटाई गई चल संपत्ति पिपरिया व बनखेड़ी क्षेत्र के लोगों को बाजार मूल्य पर बेच दी है या अभी भी बेची जा रही है।
- कुछ सामग्री किशोर भारती के पिपरिया में जनवरी 1991 में स्थापित नये कार्यालय के लिये बचा ली गई है।

जमीन-जंगल का मामला

परिसर के लगभग 40 एकड़ में किशोर भारती संस्था द्वारा अपने स्रोतों से लगाये गये सामाजिक वन एवं 80 एकड़ जमीन के मामले पर कुछ कहना आवश्यक है। सन् 1981 में संस्था की पहल पर ग्राम पलिया पिपरिया के लगभग 80 भूमिहीन व अन्य गरीब परिवारों को संगठित करके एक मजदूर संगठन* बनाया गया था। संस्था ने इस संगठन के साथ अपने औपचारिकतर (नॉन-फार्मल) शिक्षण एवं चेतना जागरण कार्यक्रम के तहत

* आज ग्राम पलिया पिपरिया का जो संगठन किसान मजदूर संगठन के नाम से जाना जाता है वह उस मजदूर संगठन से सर्वथा भिन्न है जो किशोर भारती की पहल पर सन् 1981 में शुरू हुआ था।

दो प्रक्रियाएं शुरू की थीं -

एक, लगभग 80 एकड़ जमीन के एक-एक एकड़ के भूखंड बनाकर इन पर उन परिवारों को खेती करने की अनुमति दी गई।

दो, संस्था द्वारा लगाये गये 40 एकड़ के सामाजिक वन के उत्पादन (लकड़ी, बाँस, लाख, घास आदि) को संगठन के सदस्यों को प्राथमिकता बतौर बाजार मूल्य से कुछ कम दर पर उपलब्ध कराया जाता रहा।

जब संस्था ने फरवरी 1989 में परिसर शासन को लौटाने का निर्णय लिया तो कार्यकारिणी समिति ने यह भी तय किया कि वह शासन से सहयोग लेकर इन भूखंडों का पट्टा उन पर खेती करने वाले परिवारों को निजी या सामूहिक तौर पर दिलवाने का प्रयास करेगी और संस्था के सामाजिक वन की शासकीय तंत्र में ऐसी व्यवस्था करवा देगी कि उसके उत्पादन का लाभ संगठन के सदस्यों को पूर्ववत् मिलता रहे। अगस्त 1989 में संगठन द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि इन भूखंडों का पट्टा उन्हें किसी सामूहिक व्यवस्था के तहत दिलवाया जाय, निजी तौर पर नहीं। उक्त प्रस्ताव के अनुसार संस्था ने शासन से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श शुरू कर सहकारिता के आधार पर पट्टा दिलवाने एवं जंगल की उचित व्यवस्था करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय भी करवा लिये थे। इस दिशा में राजस्व विभाग ने कार्यवाही शुरू करते हुये कलेक्टर, होशंगाबाद को प्रारंभिक निर्देश भी जारी कर दिये थे।

ऊपरोक्त ठोस प्रगति की जानकारी मिलने पर किसान मजदूर संगठन (ग्राम पलिया पिपरिया) के केन्द्रीय नेतृत्व ने समता संगठन (पिपरिया), किसान आदिवासी संगठन (केसला), किशोर भारती के कुछ पूर्व कार्यकर्ताओं एवं एकलव्य संस्था के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर हम को एक संयुक्त पत्र द्वारा सूचना दी कि किसान मजदूर संगठन जमीन व जंगल के इस मसले को सरकार से हल करवाने में पूर्णतः सक्षम है, इसलिये अब उसे इस मुद्दे पर संस्था से किसी प्रकार की मदद नहीं चाहिये। पत्र के इस आशय की पुष्टि संस्था ने संगठन की एक खुली बैठक में जाकर की व उसके बाद शासन के साथ सफलतापूर्वक चल रही बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ा। आज हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपरोक्त सभी संगठन और लोग स्वेच्छा से उठायी गयी इस सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे ताकि ग्राम पलिया पिपरिया के हरिजन-आदिवासी व अन्य गरीब परिवारों का कोई नुकसान न हो।

आडिटिंग एवं चैरिटी कमिश्नर

कार्यकारिणी समिति ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष (1990-91) के हिसाब-किताब की भी विधिवत आडिटिंग करवाई है। इस वर्ष की आडिट रपट संबंधित चैरिटी कमिश्नर एवं आयकर कार्यालय को भेजी जा चुकी है जिसमें राज्य शासन को परिसर की अचल सम्पत्ति का कब्जा सौंपने एवं संस्था की चल संपत्ति को दान देकर या बिक्री करके अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की सूचना भी शामिल है।

परिसर का भावी उपयोग

जिस परिसर का कब्जा राज्य शासन को जनवरी 1991 में सौंपा गया है उसे शिक्षा एवं कृषि संबंधी क्रियाकलापों हेतु विकसित किया गया था। उस पर कांक्र्रीट रिंग के बने नौ कुएं (स्थाई जल स्रोत वाले), कई भवन (आवास, हाल एवं गोदाम समेत), गोशाला, गोबर गैस प्लांट आदि खड़े हुये हैं। लगभग 100 एकड़ जमीन कंटीली तारों की पक्की फेंसिंग से घिरी हुई है। परिसर पर संस्था द्वारा मूल्यवान फलोद्यान एवं सामाजिक वन विकसित किये गये हैं। हमारे द्वारा करवाये गये मूल्यांकन के अनुसार शासन को सौंपी गई सम्पत्ति का आज की कीमतों पर मूल्य 30.6 लाख रुपये आंका गया है (सामाजिक वन एवं फलोद्यान का मूल्य ही लगभग 10 लाख रुपये का है)। स्पष्ट है कि संस्था को इस बात की चिंता है कि शासन इस परिसर का क्या उपयोग करेगा। हम चाहते हैं कि परिसर का उपयोग शासकीय तत्वावधान में इस अंचल के विकास हेतु इस प्रकार हो कि इसका सर्वाधिक लाभ अंचल के कमजोर तबके को प्राथमिकता बतौर मिले। हम यह भी चाहते हैं कि किशोर भारती द्वारा किये गये शैक्षिक काम की लंबी एवं समृद्ध परंपरा को देखते हुये शासन परिसर का उपयोग शिक्षा हेतु ही करे। अतः परिसर वापस करने के संबंध में राज्य शासन को भेजे गये विभिन्न पत्रों में संस्था ने लिखा है कि यदि इस परिसर पर शासकीय तत्वावधान में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय अथवा व्यावसायिक हाई स्कूल स्थापित किया जाता है तो उसके लिये संस्था हर प्रकार का समर्थन देने को तत्पर है। इसी तारतम्य में संस्था की ओर से पूरी नर्मदा घाटी के संदर्भ में आंचलिक विकास के उद्देश्य से काम करने वाले एक शोध, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का खाका तैयार करके राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया जिसमें कालांतर में इस संस्थान को ग्रामीण विश्वविद्यालय में विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल था। इन प्रस्तावों के समर्थन में अनेक स्थानीय नागरिकों ने शासन को ज्ञापन भी दिये। संस्था के प्रतिनिधियों ने भी कई बार मुख्यमंत्री, मंत्रीपरिषद के कई वरिष्ठ सदस्यों एवं स्थानीय सांसद व विधायकों से मिलकर इन प्रस्तावों से पूरे अंचल को होने वाले लाभों को

रेखांकित किया और क्रियान्वयन हेतु ठोस सुझाव भी रखे। इन प्रयासों के बावजूद राज्य शासन की इस संदर्भ में निष्क्रियता और मौन हमारी समझ के परे हैं।

आगे की बात

संस्था ने सन् 1972 से लेकर सन् 1989 तक शैक्षिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास के अभिनव प्रयोग निरंतर किये, यह आप भलीभांति जानते ही हैं। सीमेंट कांक्रीट रिगों से बने एक हजार से अधिक कुएं आज इस क्षेत्र की हजारों एकड़ जमीन को सींच रहे हैं जिसके फलस्वरूप इस जमीन में एक फसल की जगह दो या तीन फसलें ली जा रही हैं। संस्था के गोसंवर्धन कार्यक्रम के कारण ही आज इस इलाके में सैकड़ों दूधारू संकर गायें देखी जा सकती हैं। होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कई नये आयाम स्थापित करके देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस कार्यक्रम की बुनियाद पर ही 'एकलव्य' संस्था का 1982-83 में गठन किया गया जिसकी स्थापना में किशोर भारती ने केन्द्रीय भूमिका निभायी। संस्था के द्वारा चलाये गये सामाजिक चेतना जागृत करने के अनेक कार्यक्रमों का स्पष्ट प्रभाव आज पिपरिया व बनखेड़ी क्षेत्र में दिख रहा है, हालांकि कुछ कारणों से नेतृत्व की समझ एवं राजनैतिक दिशा की दृष्टि से इस उभरती हुई चेतना का मूल्यांकन करना जरूरी लगता है। संस्था द्वारा चलाये गये पुस्तकालय (विशेषकर सचल पुस्तकालय) व अन्य औपचारिकेतर शिक्षण कार्यक्रमों (उदाहरणतः युवा प्रशिक्षण, जरूरी दवाई सुविधा, प्रजनन जागरूकता, महिला चेतना, बाल गतिविधियों आदि) ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में नये मील पत्थरों का काम किया है। परंतु कुल मिलाकर इस प्रक्रिया का समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है और उससे स्वैच्छिक पहलकदमी को कैसी दिशा मिलती है, यह एक गहरे शोध का विषय होना चाहिये। संस्था निकट भविष्य में एक वस्तुनिष्ठ शोध कार्यक्रम आयोजित करने की पहल करेगी। हमारा इरादा है कि हम अपने अनुभवों को समाज के सामने इस प्रकार पेश करें कि स्वैच्छिक काम की संभावनायें, सीमायें एवं उसकी राजनैतिक भूमिका स्पष्ट रूप से उजागर हो सके।

कार्यकारिणी समिति ने यह भी तय किया है कि लगभग एक वर्ष के लिये संस्था सुप्तावस्था में रहेगी। उसके बाद तय किया जायेगा कि संस्था के पास जो संसाधन और सुविधायें अभी भी उपलब्ध हैं, उनका किस प्रकार उपयोग किया जाये।

उपसंहार

अट्ठारह वर्षों के काम को समेटना और अपनी कर्मभूमि से संस्था

को बाहर निकालना परेशानियों व पीड़ाओं के बगैर संभव हुआ हो, यह दावा तो हम नहीं कर सकते। समिति के इस निर्णय के बारे में सहमति व मतभेदों की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। एक खुली बहस चलनी ही चाहिये। किंतु एक बात पर हम अवश्य जोर देना चाहेंगे कि किशोर भारती सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रयोग था जिसको हमने तब तक चलाया जब तक हमें उसमें प्रयोग की गुंजाईश दिखी। परंतु इसके पहले कि प्रयोग दुकानदारी या मठ बन जाता (चाहे यह हमारी कमजोरियों के कारण ही क्यों न हो), हमने प्रयोग को बंद करने का निर्णय लिया और निर्णय को पक्के इरादे के साथ क्रियान्वित भी किया। यह तो भविष्य ही बतायेगा कि यह निर्णय कहां तक सही था।

किशोर भारती जैसी बहुआयामी एवं जिले स्तर पर सक्रिय संस्था का स्वेच्छा से अपने को समेट लेना भारत के स्वयंसेवी कार्यक्षेत्र के इतिहास में निःसंदेह एक अनूठी घटना है। अपनी संस्था, सम्पत्ति और कार्यक्रमों से मोह तोड़कर इस प्रकार का निर्णायक कदम उठाना किसी भी मायने में आसान काम न था। कतिपय निहित स्वार्थों एवं दिग्भ्रमित तत्वों द्वारा इस प्रक्रिया में जो अवरोध पैदा किये गये, वे अनपेक्षित नहीं थे और उनके कारण इस निर्णय के औचित्य में हमारा विश्वास और भी अधिक गहरा हुआ। आमतौर पर स्वैच्छिक संस्थाओं की यह नियति रही है कि अपने शिखर पर पहुंचने के बाद उनके नैतिक बल एवं गुणवत्ता में गिरावट आती है। उस स्थिति में संस्था में उपस्थित स्वार्थी तत्व मठाधीश बन जाते हैं। इस संदर्भ में किशोर भारती द्वारा समय रहते अपने को समेट लेने का निर्णय अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के लिये अध्ययन का विषय होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यदि अन्य समानधर्मी संस्थायें भी सामाजिक परिवर्तन में अपनी संभावनाओं एवं सीमाओं को वस्तुनिष्ठ ढंग से पहचान सकें तो स्वैच्छिक कार्यक्षेत्र की राजनैतिक भूमिका का वैज्ञानिक प्रतिपादन संभव हो सकेगा।

इस लंबी अवधि में आप सबने संस्था को आगे बढ़ाने के लिये जो भी सहयोग दिया वह हमारे लिये अमूल्य धरोहर है। इस संदर्भ में एक सार्वजनिक संस्था का सबसे बड़ा दायित्व यही बनता है कि वह अपने अनुभवों का विवरण व विश्लेषण देश की मौजूदा हालातों के परिप्रेक्ष्य में सबके सामने ईमानदारी एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रस्तुत करे। इस दायित्व को पूरा करने के लिये हम संकल्पशील हैं।

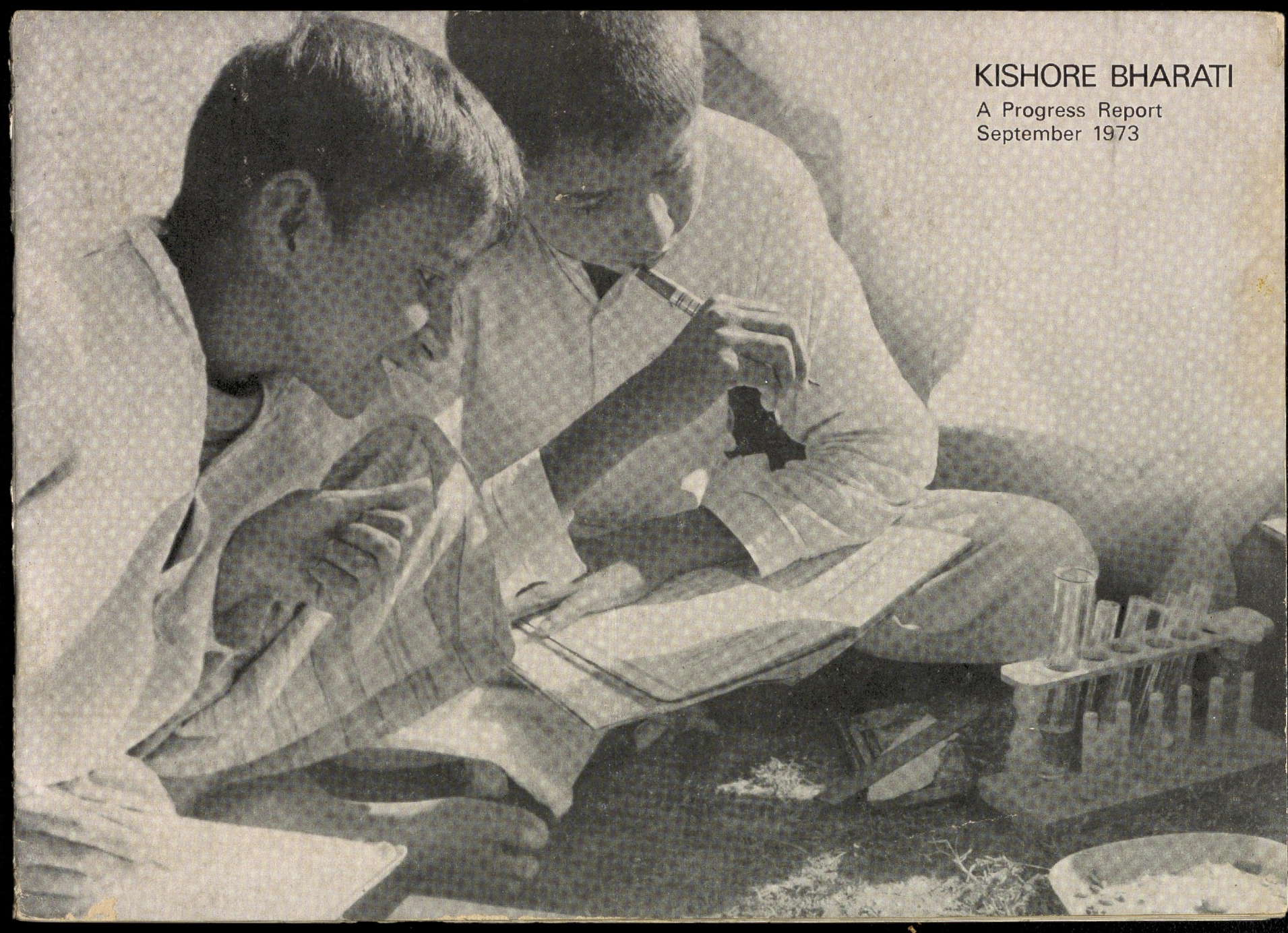
कार्यकारिणी समिति

(1991-92)

नाम	व्यवसाय	पता	पद
1. सुश्री अनुसुइया दत्त	अधिवक्ता	4. मिस्त्री कोर्ट दिनशा वाच्छा रोड, चर्च गेट, बंबई 400020	सदस्य
2. श्री ज्योतिभाई देसाई	शिक्षक / समाजकर्मी	गांधी विद्यापीठ, वेडछी, जिला सूरत, गुजरात 394640	सदस्य
3. डॉ. वासू नोरी	स्ट्रक्चरल इंजीनियर	13. वसंत महल, सी रोड, चर्चगेट, बंबई 400020	सदस्य
4. श्री श्याम बोहरे	शिक्षक / प्रशिक्षक	ई-12, प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016	कोषाध्यक्ष
5. श्री सुभाष शाह	अधिवक्ता	सी- 83 वीनस अपार्टमेंट्स, आर. जी. धडाणी मार्ग, वर्ली, बंबई 400018	अध्यक्ष
6. डॉ. अनिल सद्गोपाल	वैज्ञानिक / शिक्षाविद्	ई-13, कालिंदी, नई दिल्ली 110065	सदस्य
7. श्री राजेन्द्र हरदेनिया	पत्रकार / व्यापार	अर्चना कृषि केन्द्र, शोभापुर रोड, पिपरिया, म.प्र. 461775	सचिव
8. डॉ. विजय वर्मा	वैज्ञानिक / शिक्षक	भौतिक शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007	सदस्य
9. श्री बलदेव सिन्धू	परिवहन / फ़ायनेंसिंग	बी- 2/12 माडल टाऊन, दिल्ली 110009	विशेष आमंत्रित
10. श्री सुरेश सुरतवाला	समाजकर्मी	34, नूतन लक्ष्मी सोसायटी, 10 वीं रोड, जुहु स्क्रीम, बंबई 400049	विशेष आमंत्रित

KISHORE BHARATI

A Progress Report
September 1973



This is the second Progress Report since the beginning of our work. The first was released in November, 1971, and is available on request.

All communications and contributions may be sent to:
KISHORE BHARATI
P. O. Malhanwara
Via Bankheri
Dist. Hoshangabad
Madhya Pradesh 461990

Kishore Bharati is an experiment in rural education and development based in Hoshangabad District, Madhya Pradesh. Over the last few years, we have been analysing voluntary and Government attempts made in this direction. Through these explorations and our own local experience, we have arrived at a double-pronged approach to social change in the villages. We must create an economic infrastructure, and, we must radically overhaul the present education system to suit village conditions. In this manner, we would hope to reverse the fruitless city-bound migration of village youth in search of scarce menial jobs.

Whatever we do at Kishore Bharati is guided by the principle that the relationship we build up with the surrounding population be totally free of any touch of charity, patronage or dependence on us. Our actions must encourage local initiative and promote grassroots organisation. The clearest indication of success will be the speed with which the villagers assume responsibility for their own development and thus, render us superfluous.

The underlying assumption of all this work is that it is still possible to bring about relevant changes within the present socio-political structure. After weighing several alternatives, we have accepted this constraint. It remains to be seen whether any impregnable barriers inherent in the system will come in the way of achieving our objectives. If such barriers do appear, the primary assumption will have to be seriously questioned.

We thank all those who have given us their time, energies and money to help us progress towards our objectives. Yet the task has only begun. As we accelerate the pace of our work and take up new responsibilities, we look forward to your continuous and generous support. Our need for motivated and talented people willing to work and live in rural areas is just as urgent as ever.

We record our special thanks to the district authorities of Hoshangabad, various departments and agencies of the Government of Madhya Pradesh and the Central Government for the support given to us in starting a number of our projects.

We express our appreciation for the help which we have been getting from the local farmers for the last one year. It is this kind of help which encourages us to continue what we are doing with greater hope and meaning.

When Kishore Bharati was being conceived, it was decided as a matter of policy to seek financial support and manpower from Indian sources alone. We continue to feel that unless our own countrymen get fully involved and share the responsibility of carrying out such work, we shall not succeed in solving our basic economic and social problems. It is evident that there is more than enough money in the country to catalyse rural development, if only we learn to channel this money properly.

Kishore Bharati began its fund-raising drive in December, 1970. Since then a total of about Rs. 3.5 lakhs have been raised in cash and kind. Contributions from individuals have ranged from Rs. 5 to Rs. 2,000 and those from corporate sources such as firms, companies, trusts and student groups, from Rs. 500 to Rs. 60,000 (see Appendix II). We need to raise at least Rs. 5 lakhs during the current year in order to implement the proposed programmes. Your co-operation in rapidly achieving this goal will enable us to look ahead and work with renewed confidence.

All contributions to Kishore Bharati are deductible under Section 80 (G) of the Income Tax Act, 1961.

Please send your donations in the name of KISHORE BHARATI either by crossed cheque to our address (inside front cover) or through a mail transfer to our Home Savings Account No. 704 with the Central Bank of India, Hoshangabad, M. P. 461001.

Contents

1. Plan of Action	4
2. Location	4
3. Beginnings	4
4. Farming	5
5. Ringwells	5
6. Irrigation Programme	6
7. Cattle Development Programme	6
8. Cement Unit	7
9. An Experiment in Cottage Industry	8
10. Vocation-Based Education Programme	8
11. Science Teaching Programme	8
12. Building Plan	10
13. Staff Members	10
14. Volunteers	11
15. Executive Committee (1973-74)	12
Appendix I	14
A list of the Scientists and Teacher-trainers Participating in the Science Teaching Programme	
Appendix II	16
Fund-Raising Drive — A Summary	

Cover

Discovery : Children in a village school covered by the Science Teaching Programme

Plan of Action

It has been our attempt to look at a region—rather than isolated villages—as a practical unit of development. To date, we have identified irrigation, milch cattle and cottage and small-scale industries as three major inputs which are crucial to the economic development of this region. Search is also on for a system of credit and marketing that will make it possible for small and marginal farmers and landless labour to participate in these development programmes. In education, we are working at two levels simultaneously. Within the existing school system, we have undertaken to optimise a free thinking spirit and develop the capacity for self-learning in children. Outside the Government structure, our effort is to evolve a wholly new pattern of vocation-based education. Here, we propose to combine academic and vocational training in such a way that it will infuse self-confidence amongst

young villagers in the viability of agro-based activities and, at the same time, strengthen their faith in co-operative endeavour as an effective means of solving community problems.

Location

Kishore Bharati received 150 acres of land in Hoshangabad District from the Government of Madhya Pradesh in March, 1972. The location is Palia Piparia village, about 17 miles east of Piparia and 4 miles from Bankhedj on the Piparia-Jabalpur road. Both Piparia and Bankhedj, towns with populations of about 25,000 and 5,000 respectively, are on the Bombay-Howrah railway line via Allahabad.

The transfer of land took place despite concerted opposition from local vested interests, both landed and political.

Fearing direct financial losses and gradual attrition of their traditional hold in the area, they exerted their influence in administrative and political circles to block the Government from releasing the land. They also succeeded in casting widespread fear and misgivings about Kishore Bharati amongst the local population. It was in such an uncertain atmosphere that the first three staff members, Devta Deen Mishra, Sankata Prasad and Anil Sadgopal, moved to the new site on May 1, 1972, to start the work. Gradually, as a result of daily contact with the people and the work on the site, early feelings of suspicion and non-co-operation have largely disappeared.

Beginnings

Our life in Palia Piparia village began

under a big kausum tree. We soon built a thatched hut in which we lived throughout the entire monsoons of 1972. We have now moved into two multipurpose buildings with tiled roofing. These single-storeyed hall-like structures have been partitioned to serve as a dormitory for staff members, office, store, kitchen and dining space, a small science laboratory and library, and a room for training boys in the manufacture of electrical items.

Farming

Our first problem was to remove tree stumps—an average of 300 per acre—left behind when the Government felled the trees before handing over the land. Since machinery for this task was not available, the stumps were removed manually. Fifty-six acres were thus cleared in less than six weeks during the short spell of monsoons last year. The average cost of removing stumps was about Rs. 120 per acre. Work on the removal of stumps from the remaining 94 acres is being organised right now and will be completed by the end of this rainy season.

The agricultural operations began within a couple of months of the transfer of land last year. Twelve acres were put under

a mixed crop of **tuar** and **til** in the kharif of 1972. During the rabi, eight acres were sown with dwarf varieties of wheat. Our first attempt at cultivating the land was made particularly difficult by the high incidence of white ants, low humus content, poor water-retaining capacity of sandy soil and lack of fencing. Due to delay in getting the electricity connection to our well last year, the **tuar** and **til** crops had to depend totally on the scanty rains of the monsoons. In spite of all this, we managed to make a small profit.

During the current kharif season, we have sown 21 acres with groundnut, 3 acres with soyabean and a couple of acres with fodder crops (corn and napier grass).

Meanwhile, plans are afoot to conduct a contour survey with the help of Government surveyors. As soon as this is completed, the land will be levelled and irrigation channels laid on scientific lines. We propose to cultivate 100 acres in the next rabi, ultimately covering most of the 150 acres by 1974.

One of our chief problems in agriculture is the absence of fencing. This has already resulted in significant losses caused by stray cattle. The estimated cost of fencing the entire land is about Rs. 1.5 lakhs.

Raising support for this is one of our top priorities.

Ring Wells

In April, 1972, we sank an open well of 4 feet diameter, lined with pre-cast cement rings. It is of a design conceived of and popularised by Friends Rural Centre, a voluntary agency that has been concerned with rural education and development in Hoshangabad District for the past several years. The well, which gives a yield of about 10,000 gallons of water per hour, has become the talk of the villages in the area because of its low cost of construction and the speed with which it was completed. More recently, we have dug 8 additional wells on the site, and plan to complete another 4 by the end of this year. The nine wells already completed will assure irrigation for at least 100 acres, leaving us with a possible surplus for the neighboring farmers. The average cost of such a ring well along with an electric pumpset is about Rs. 5,200. We have thus been able to provide irrigation to 100 acres at a cost of less than Rs. 500 per acre.

Irrigation Programme

Farmers who frequently visit the site to see the ring wells, have expressed the wish to have similar ones on their farms. In response to this felt need, we began manufacturing cement rings in December 1972. There is a brisk sale of rings at Kishore Bharati today. Eight farmers of Palia Piparia village and eight more from surrounding villages have already acquired such wells, with the result that their income per acre is likely to increase by a factor of at least 2 or 3 this year.

We would like to point out two important features of this activity. Firstly, it is an example of the kind of small-scale industry that boys from landless labour families can profitably take up, especially if bank credit is made available to them. Secondly, ring wells, unlike tubewells, are within the grasp of a small farmer and enable him to go in for high yielding crops such as dwarf varieties of wheat which need assured irrigation. To cite an example, three of our neighbouring farmers, whose combined holdings add up to 8 acres, were induced to switch over to dwarf varieties of wheat during the last rabi season because we supplied them water from our well. We hope to release water on a larger scale later this year. A number of farmers

are looking forward to this so that they can earn enough money on their rabi crops to afford a ring well of their own next year.

We are presently looking around for help to procure a couple of drainage pumpsets along with a generator so that Kishore Bharati staff can go into the surrounding villages and assist farmers to deepen their wells, a necessary operation in the construction of successful ring wells. When, and if, this facility becomes available to us, we will be in a position to make a major contribution to increasing the irrigation potential, and consequently the agricultural production, of the Bankhedi region.

Cattle Development Programme

We have concerned ourselves with the development of dairying both because it supplements farming operations and since it provides a regular income to the farmer. An expert from AMUL (Anand, Kaira District, Gujarat), who surveyed Hoshangabad District in October, 1971, reported that there was hardly any surplus milk in the area, and that, therefore, an economically viable milk marketing co-operative was not presently feasible.

Genetically poor milch stock and inadequate feeding and management practices are some of the reasons for low milk production. We are, therefore, organising a programme of cattle development to create a milk surplus in the area. As milk production goes up, a marketing co-operative on the lines of AMUL could be started.

The pivot of our effort will be cross-breeding of local cows using frozen semen from progeny-tested plus bulls of high genetic potential. Experience in several centres in Maharashtra has shown that a local cow with a lactation yield of about 300 litres per year can lead to progeny whose lactation yield could be as high as 2,500 litres per year. Artificial insemination, a veterinary service, encouragement to grow fodder crops and training in better management practices will be the cornerstones of this programme. To convince the farmers of the effectiveness of new ideas, a demonstration-cum-training farm of cross-bred cows is being set up. A cattle development centre will be organised later from where the facilities for artificial insemination and veterinary care shall be taken to the doorstep of the farmer. In a period of three years, the programme will cover 2,000 cows in an area of ten miles radius. All this

work is being done with the technical guidance of the Bharatiya Agro-Industries Foundation, Uruli Kanchan, Poona District, Maharashtra.

An intensive effort is under way to win the support of the farmers for the proposed cattle development programme. The following steps are being taken to achieve this goal.

1. Frequent meetings are being held, both at Kishore Bharati and in the villages, to talk about the tremendous potential of cross-breeding and to discuss the ways in which the farmers could contribute towards the cost of the programme.

2. A half-bred bull (Tharparkar X Holstein-Fresian) has been brought to Kishore Bharati to emphasise the role of cross-breeding. A male calf, sired by this bull, has also come to Kishore Bharati along with his Red Sindhi mother. The cross-bred animals have rapidly attracted attention due to their high growth rate and expected genetic potential. The half-bred bull, who has already started servicing the local cows, is expected to pave the way for a cross-breeding programme based on artificial insemination. When this happens, liquid nitrogen tanks containing frozen semen

from progeny-tested bulls will take his place.

3. To popularise the use of fodder crops, an acre of land was sown with lucerne during the last rabi and a couple of acres have been sown with corn and napier grass in the current kharif season.

4. At an appropriate stage, groups of farmers will be taken to dairy centres like AMUL, Bharatiya Agro-Industries Foundation and J. N. Krishi Vishwa Vidyalaya (Jabalpur), where they can see the role of cross-breeding and milk marketing in transforming rural economy.

5. Eight local cows of poor genetic background have been procured from the farmers for a demonstration programme. At present they are being kept at Friends Rural Centre, Rasulia, which has the facilities for artificial insemination with semen from progeny-tested bulls. When pregnant, these cows will be brought to Kishore Bharati. It is expected that the high milk-yielding progeny of such local cows will make a visible impact and help to convince the farmers of the effectiveness of this programme.

The initial capital investment for setting up a demonstration-cum-training cattle farm and a cattle development centre

will be about Rs. 1 lakh. The annual recurring expenditure for running a cattle development centre is Rs. 35,000. Over a period of three years the cost of running such a centre will be met through contributions from the farmers participating in the programme. The recurring expenditure for the first two years, however, needs to be guaranteed through donations or grants; this money can later be used as a revolving fund for setting up new cattle development centres in the region. The ultimate thrust of this programme is to make it possible for the small and marginal farmer—one who has, say, a single cow—to gain from the advent of dairy technology. We are exploring the possibility of credit support to the farmers to enable them to meet the cost of breeding, feeding and veterinary facilities. Search is also on for a suitable type of farmers' association, co-operative or otherwise, which will encourage local initiative in cattle development and milk marketing.

Cement Unit

The main activity of this unit is the production of rings for wells. Economical water-sealed latrines, needing little water to flush, are also being made, and we

plan to manufacture irrigation channels and fence posts as well. Although the cement unit operated for merely four months during the financial year ending on March 31, 1973, products worth almost Rs. 20,000 were made.

An Experiment in Cottage Industry

Ravi Chugh, a staff member, went to Faridabad to learn about the manufacture of chokes for tubelights. He has returned to Kishore Bharati and is presently organising a production-cum-training programme. The first few samples have already been made under local conditions and shown to work. Once again, this is a scheme specially suited for boys from families with little or no land. Training completed, these boys will return to their homes with credit support for buying their own hand-operated winding machines.

The success of this venture depends upon finding access to stable markets. We are in touch with some leading manufacturers of tubelights and hope to set up an arrangement whereby Kishore Bharati will initially be responsible for quality testing and marketing. It is envisaged that this programme will provide us with guidelines for organising a

variety of cottage industries on a similar basis.

Vocation-Based Education Programme

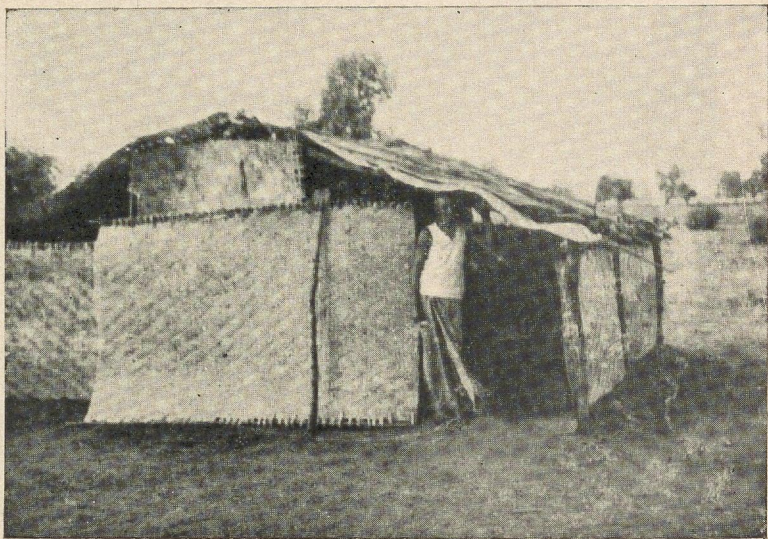
Our study of the villages reveals that this programme will have to concern itself mainly with the dropouts from the schools. A vast majority of educational authorities look upon these dropouts as a major national problem. Immense efforts are going to be made during the coming five-year plans to pull back the dropouts into the conventional education system. We are convinced, however, that the dropouts are an asset rather than a liability. Having escaped from the irrelevant and monotonous education of the schools, the dropouts have the benefit of being exposed to the social and economic realities of daily life in the villages. They offer, therefore, a better potential for growth than their counterparts in the schools. We intend to exploit this opportunity by offering the dropouts of the surrounding villages a vocation-based education which will be aimed at infusing in them a spirit of self-reliance and co-operation. In contrast to the school system, this education will be centred around productive activities like farming,

dairying, cottage industries, workshop and marketing.

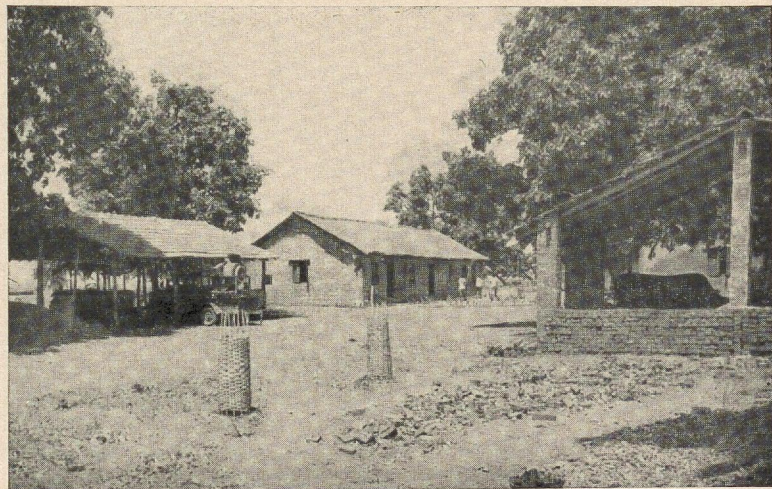
It is important to emphasise here that a vocation-based education programme for the villages can be meaningful only if it is integrated with the effort to create a regional economic infrastructure. A vocational education programme without a simultaneous economic development effort is likely to be as irrelevant and unproductive as the existing school system. In fact, economic development projects in a region are themselves the most suitable training grounds for young people. It is for this reason that Kishore Bharati has first concentrated on organising a few crucial projects of economic development. Within the next few months, we are hoping to reach the stage when a vocation-based education programme will become not only meaningful and practical but also crucial to further development. Search for the first batch of students has already begun.

Science Teaching Programme

Although Kishore Bharati's central aim is to organise a relevant rural educational programme outside the existing educational structure, the multitudes of children



1



3



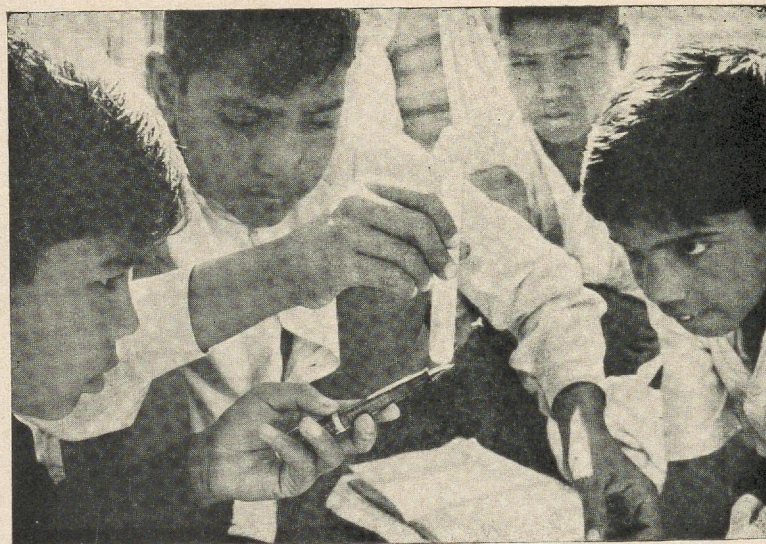
2

From Small Beginnings

- 1 May '72 — The first shelter
- 2 Kishore Bharati becomes visible on the Piparia-Gadarwara Road
- 3 Today



1



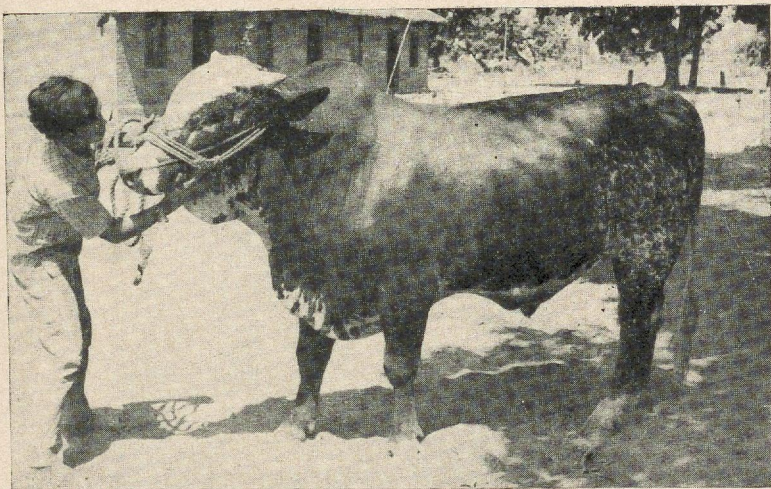
2



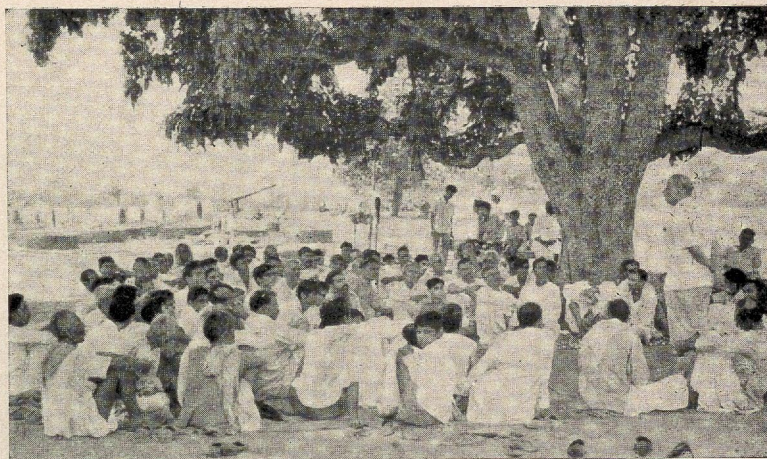
3

Science Teaching Programme

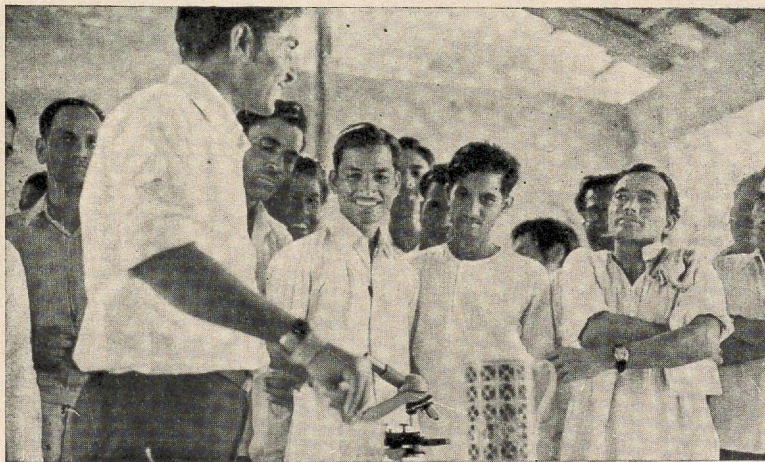
- 1 A village teacher helps children conduct an experiment on volume
- 2 Testing for starch in food materials
- 3 Village teachers with visiting scientists and teacher-trainers at a monthly meeting



1



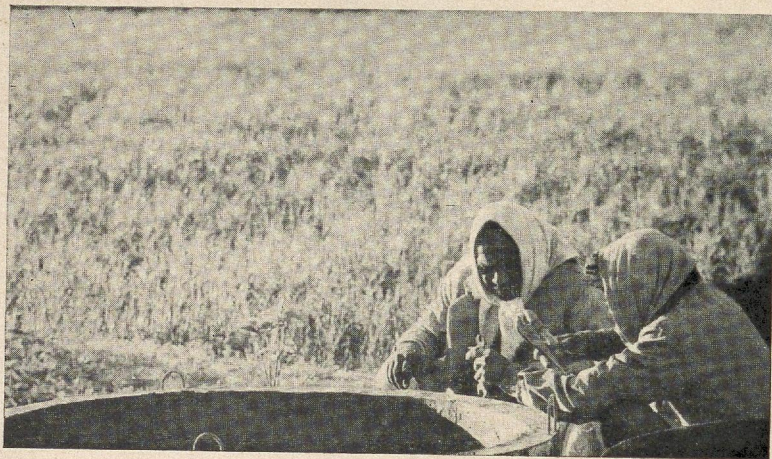
2



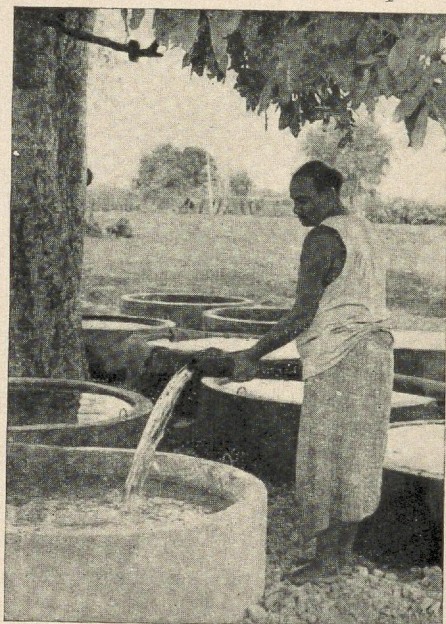
3

Cattle Development Programme

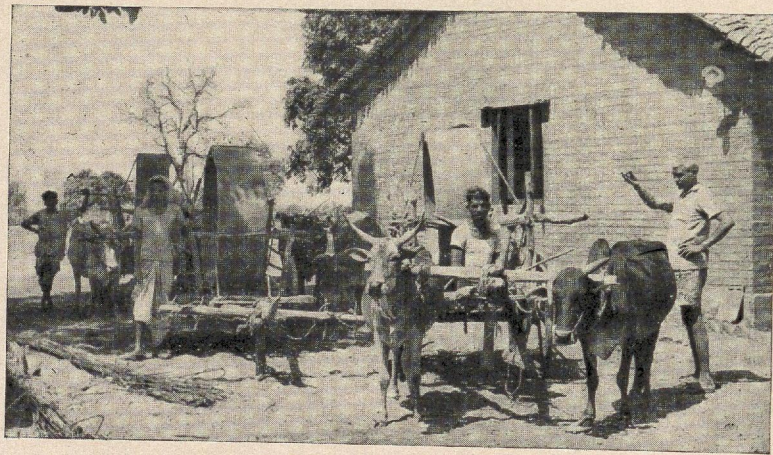
- 1 Ghanshyam — a Tharparkar X Holstein-Fresian half-bred bull used for servicing local cows
- 2 Villagers gather from afar to participate in a meeting addressed by a visiting cattle expert
- 3 "What is *artificial insemination*?" — a veterinarian explains to a group of amused science teachers



1



2



3

Ring Well Programme

- 1 December '72 — The first cement ring takes shape at Kishore Bharati
- 2 Rings being watered for curing
- 3 "Jai Ramji!" — a villager departing with his caravan of rings

attending the conventional schools cannot, and should not, be ignored. The need to find ways of transforming the methods of education within the school system continues to pose a major national challenge. It was with this feeling that Kishore Bharati decided last year to start an effort to change science teaching methods in the surrounding schools. The programme, a joint effort of Kishore Bharati and Friends Rural Centre, aims to introduce science teaching through experiments and inquiry with the cooperation of an average village teacher.

The Government of Madhya Pradesh has released 16 rural middle schools for this programme. Nine of these schools are located around Friends Rural Centre in Hoshangabad Tahsil and seven of them around Kishore Bharati in Sohagpur Tahsil. The Government has given us full freedom to experiment with text-books, syllabi, learning methods and the examination system, and to devise teacher-training techniques.

The First Year: In May-June, 1972, with the help of members of the All India Science Teachers' Association Physics Study Group and several scientists of the Tata Institute of Fundamental Research (Bombay), we held a three-week Orientation Course for 34 teachers from these

schools. The majority of these teachers have had little or no background in science. During the Orientation Course, the teachers were trained in science teaching methods which allow the children to learn through their own observations and conclusions. An inexpensive but highly versatile kit has been distributed to these schools along with a workbook. The work-book, specially designed to utilise the village environment, differs from ordinary text-books in that it contains no facts or definitions. It is merely a set of instructions to the children for performing experiments, followed by a few guiding questions. The core of the programme is an intensive follow-up effort involving one-day monthly meetings with the teachers and frequent visits to individual classrooms to come in direct contact with the children. The feedback thus collected has given us new insights into the problem of carrying the discovery method of learning science to rural teachers and children. The first year's material is being revised both in content and direction on the basis of this feedback.

The Second Year: During the first year, the trials were conducted in class six, involving about 750 children. The number of children has increased to 1,400 this year as the programme has

been taken to class seven. The second Orientation Course was held in May-June, 1973. A special feature of this year is the introduction of the concept of individual science projects to encourage the students to develop their own style and pace of learning. The teachers and the students will be further encouraged to organise science exhibitions in the villages to involve the entire community.

The Future : The Government of Madhya Pradesh has recently proposed that we demonstrate the efficacy and relevance of the programme by expanding it to all of the 150 middle schools of Hoshangabad District. We are presently trying to build up a nucleus of workers to take up this challenge. We are also alive to the need for including the primary schools in this effort and to cover mathematics and languages—the two subjects which are essential to better understanding and communication in science. Our long-range goal is to build up a group of teacher-trainers from amongst the teachers involved in our programme so that a multiplier effect is generated.

Participation by the Academic Community: A number of highly motivated scientists and teacher-trainers from the All India Science Teachers' Association, Aligarh Muslim University,

Bombay Municipal Corporation, Gandhi Vidyapeeth (Vedchhi, Surat Dist., Gujarat), Lok Bharati (Sanosra, Bhavnagar Dist., Gujarat), Space Applications Centre (Ahmedabad), Tata Institute of Fundamental Research and the Universities of Delhi and Rajasthan have visited Hoshangabad to participate in the Orientation Courses and the monthly follow-up meetings. The University of Delhi, supported by the University Grants Commission, has recently accepted a proposal that two of its faculty members be given official leave on a rotational basis for a period of six months each to work in Hoshangabad District. The first two scientists from the University of Delhi, Dr. Raj Rup and Dr. Vijay Varma, have already arrived to lead the programme. Participation of such people has helped us both to broaden the outlook of our science teachers and to involve more like-minded people from all over the country in our attempt to change the education system.

An Integrated Endeavour: For us, the Science Teaching Programme is an integral part of our other development efforts. The science teaching activity strengthens, and in turn derives strength from, these other programmes. It is in this totality that the effort to encourage a free thinking and questioning spirit

amongst the village children acquires added meaning and perspective.

Building Plan

A complete campus is being planned. The two hall-like structures now in use will eventually be vacated for a workshop and related activities. Some facilities, such as cattle sheds, agricultural stores, offices and staff residences (at present the staff members share a dormitory), are urgently needed. It was planned to begin the new construction in April, 1973, and in anticipation we have made a couple of lakhs of bricks on the site. However, the building plan is being indefinitely shelved due to an acute shortage of funds.

Staff Members

Sankata Prasad and **Devta Deen Mishra** are experienced village extension workers from a Sarvodaya project in Mirzapur District, Uttar Pradesh. Sankata looks after the Cement Unit, Brick Kiln work and construction of buildings, and deals with the Block Development people whenever necessary. Devta manages the

farm and leads the extension work for the cattle development programme.

Anil Sadgopal, who has a Ph.D. in Biochemistry from the California Institute of Technology, USA, and has worked in the Molecular Biology Unit of the Tata Institute of Fundamental Research, is over-all co-ordinator of the project and particularly involved in the educational programme.

Ravi Chugh, experienced in working with machines, has been trained in a Faridabad industry in the manufacture of chokes and will soon initiate the project. In addition, he assists in office administration.

Dalpat Danidharia has a B. A. in Rural Studies, with special training in animal husbandry, from Lok Bharati, Gujarat. He is chiefly responsible for the activities of the cattle development programme.

Anand Patwardhan, who is a graduate in Sociology from Brandeis University, USA, and has worked with a farm-workers' union under the leadership of Cesar Chavez in California, is mainly concerned with education and the social problems of the villages.

Rex D'Rozario, until recently Sub-editor

of Science Today (a Times of India Publication from Bombay), is experienced in journalism and mass communication methods. At Kishore Bharati, he assists in the farm and shares responsibilities in fund-raising and related work. Rex will also be starting work on the preparation of audio-visual aids for the Science Teaching Programme.

Jagdish Mishra, an experienced accountant from the Sarvodaya movement, is stationed at Friends Rural Centre. He spends part of his time maintaining Kishore Bharati's accounts.

Anita Anand, Sundar Burra and Rashid Shaikh, shared between Friends Rural Centre and Kishore Bharati, were with us until recently. Anita, a graduate in Education from the University of Calcutta, was largely responsible for the administration of the Science Teaching Programme during its early stages. Sundar, a graduate in Philosophy from Brandeis University, USA, looked after the fund-raising work and helped in administration. Rashid, an M.Sc. from the Indian Institute of Technology at Kanpur, was responsible for the follow-up and development of the kit and work-book for the Science Teaching Programme.

Volunteers

Nandita Haksar, a young graduate from Delhi, was with us for a month during the Orientation Course this year. She helped with the office work and in the preparation of the school kits for the Science Teaching Programme.

Sudarshan Kapur, Co-ordinator of the Friends Rural Centre, has spent a great deal of his energies in helping us to procure the land, and to plan the farming, irrigation and cattle development programmes. He also shares the administrative responsibilities of the Science Teaching Programme. Sudarshan's help in winning the backing and trust of the local people is particularly appreciated.

Ishwarbhai Rawal and Popatbhai Savani, students of Horticulture and Rural Co-operation respectively at Lok Bharati, spent a month each at Kishore Bharati. Ishwarbhai started a nursery and garden and Popatbhai assisted on the farm.

Subhash Shah, a lawyer from Bombay, looks after Kishore Bharati's legal affairs and fund-raising. We have continuously benefitted from his willing support and advice.

Asha Sippy, who was at the Friends Rural Centre until recently, has given us invaluable support by looking after Kishore Bharati's correspondence and by helping in the fund-raising work.

Executive Committee (1973-74)

Name & Address	Organisation associated with	Profession	Office Held
1. Shri Mahesh Bhogilal 4-B, Manek, Nepean Rd. Bombay 400006	Shree Ram Mills Ltd., Batliboi & Co. Priv. Ltd.	Business Management & Industry	Member
2. Shri Jyotibhai Desai Gandhi Vidyapeeth, Vedchhi District Surat Gujarat 394640	Gandhi Vidyapeeth	Rural Education & Sarvodaya Work	Chairman
3. Smt. Ansuya Dutt Bombay Mutual Chambers 5th Fl., 19-21 Hamam St. Bombay 400001	—	Law	Member
4. Dr. Vasu Nori Flat No. 13, 2nd Floor Vasant Mahal 'C' Road, Churchgate Bombay 400020	Shirish Patel & Associates	Structural Engineering	Member
5. Dr. (Smt.) Shubhada Pandya Asstt. Dean's Bungalow K. E. M. Hospital, Parel Bombay 400012	Acworth Leprosy Hospital	Medical Research	Treasurer

Name & Address	Organisation associated with	Profession	Office Held
6. Dr. Anil Sadgopal Kishore Bharati P. O. Malhanwara, Via Bankheri District Hoshangabad M. P. 461990	Kishore Bharati	Science & Rural Development	Secretary
7. Shri Baldev Sidhu B2/12 Model Town Delhi 110009	Sibo Agencies	Business	Member
8. Shri Suresh Suratwala P.O. Devapur Taluka Man District Satara Maharashtra	Sir Dorabji Tata Trust	Rural Development	Member

Smt. Geeta Athreya (Calcutta), Shri Ramesh Kundalia (Hyderabad) and Shri Subhash Shah (Bombay) have all been members of the Executive Committee for varying lengths of time in the past.

Appendix I

A List of the Scientists and Teacher-Trainers Participating in the Science Teaching Programme.

The following is a list of people who have given us help and guidance in the Science Teaching Programme since its inception in May, 1972. Many of these have participated in the Orientation Courses held so far, monthly meetings with the teachers, follow-up visits to the schools and in preparation of the kit and the work-books.

In 1972-73

Physics Study Group, All India Science Teachers' Association

1. Shri C. K. Dikshit,
The Doon School, Dehra Dun
2. Shri B. G. Pitre,
The Doon School, Dehra Dun

Department of Education, Bombay Municipal Corporation

3. Shri V. M. Phanshe,
Inspector of Schools

Editorial Board, Hindi Vigyan Sahitya Parishad, Bhabha Atomic Research Centre, Bombay 400085

4. Shri S. R. Pande
5. Shri M. Saksena

Tata Institute of Fundamental Research, Bombay 400005

Solid State Physics Group

6. Shri V. G. Kulkarni

Molecular Biology Unit

7. Dr. S. Chakraborty
8. Dr. R. S. Gupta
9. Dr. M. M. Johri
10. Dr. P. K. Maitra
11. Prof. O. Siddiqi
12. Dr. U. N. Singh

Space Applications Centre, Ahmedabad

13. Shri A. Ramaprasad
14. Prof. Yash Pal

Lok Bharati, Sanosra Bhavnagar Dist., Gujarat

15. Shri Praveen Mashruwala

Aligarh Muslim University

Department of Psychology

16. Prof. B. Mehdi

In 1973-74

Physics Study Group, All India Science Teachers' Association

1. Shri C. K. Dikshit,
The Doon School, Dehra Dun
2. Shri B. G. Pitre,
The Doon School, Dehra Dun

Tata Institute of Fundamental Research, Bombay 400005

Chemical Physics Group

3. Shri P. Ganguli

Molecular Biology Unit

4. Dr. S. Chakraborty

Solid State Physics Laboratory, Ministry of Defence, Delhi 110007

5. Shri D. K. Garg

**Publication and Information Directorate,
CSIR, New Delhi 110012**

6. Shri H. C. Jain

University of Rajasthan, Jaipur

Department of Physics

18. Prof. B. Saraf

University of Delhi, Delhi 110007

Department of Physics

7. Shri Kamal Mahendroo
8. Dr. N. Panchapakesan
9. Dr. Raj Rup
10. Dr. P. K. Srivastava
11. Dr. V. S. Varma

Department of Chemistry

12. Shri A. Kapoor
13. Dr. M. M. Kapoor
14. Dr. K. V. Sane

Department of Botany

15. Dr. V. S. Jaiswal

Department of Zoology

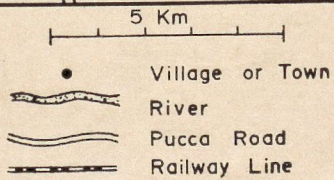
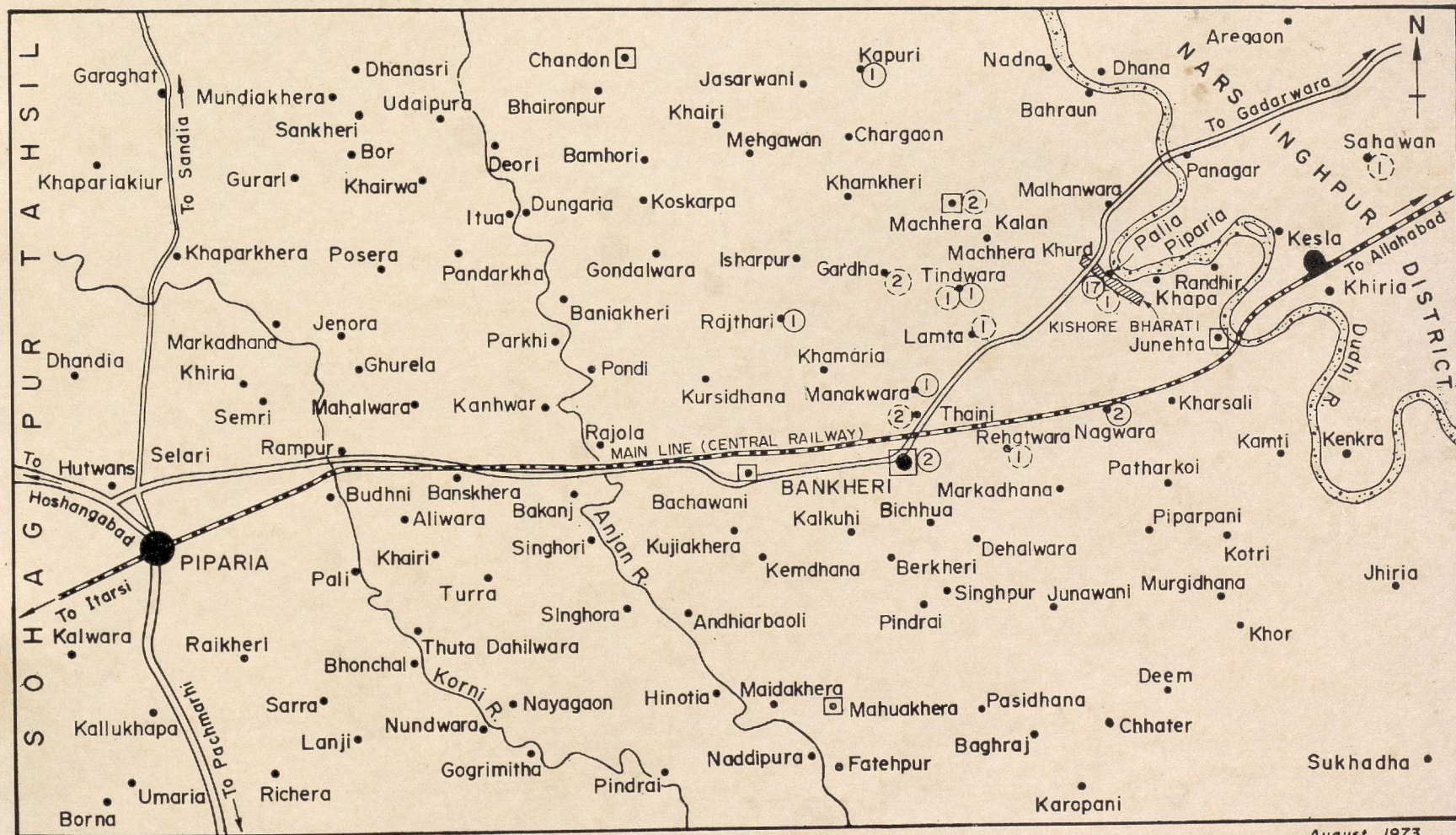
16. Shri K. K. Gothi
17. Dr. H. S. Vishnoi





Appendix II Fund-Raising Drive: A Summary

A summary of donations (in rupees) from different sources is given below.

	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	Total
Corporate Donors					
I. Companies & Firms	351	42,751	67,620	500	111,222
II. Trusts	7,001	45,500	103,995	500	156,996
III. Student Associations and Groups	50	19,267	3,315	3,811	26,443
Individual Donors	17,002	18,285	8,680	4,897	48,864
Total	24,404	125,803	183,610	9,708	343,525

A SKETCH MAP OF AREA AROUND KISHORE BHARATI



-  KISHORE BHARATI SITE
-  Covered by Science Teaching Programme (schools of Hoshangabad Tahsil not shown here)
-  Covered by Irrigation Programme, Figure indicates number of Ring Wells completed
-  Covered by Irrigation Programme, Figure indicates number of wells deepened with rings

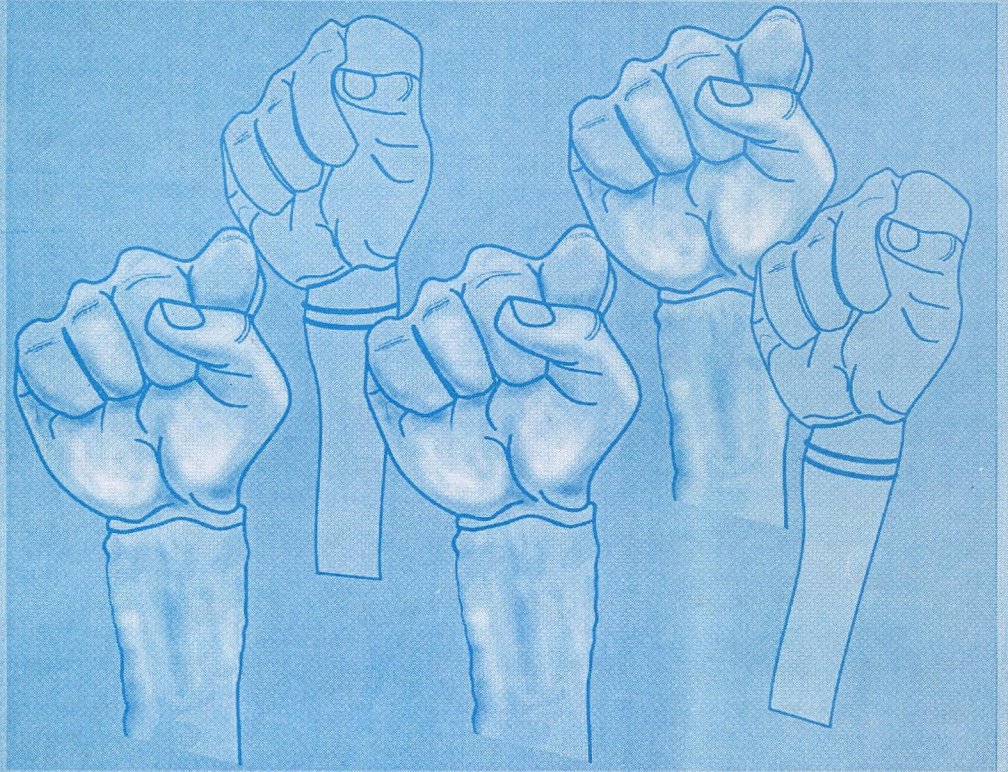
August 1973.



Printed by
Sangam Press Ltd
17B Kothrud
Poona 411 029

दरखवाला

शैक्षिक विचारों का संवाद पत्र



किशोर भारती-सरोकार
भोपाल, मध्यप्रदेश

संवाद पत्र-1

फरवरी-2010

‘दखल’

संवाद पत्र 1, फरवरी 2010

संपादन: मोहित कुमार

सहयोग: उमेश कुमार, शेख, सोनम, लेकेश, गौतम

आवृत्ति: त्रैमासिक

प्रकाशन एवं वितरण : किशोर भारती ‘सरोकार’

ई-8/29, सहकार नगर
भोपाल 462039 मध्य प्रदेश

ईमेल: kbsarokaar@gmail.com

फोन: 0755-2560438

मुद्रण: राजकमल आफसेट प्रिंटर्स
जे.के. रोड, गोविन्दपुरा
भोपाल, मध्य प्रदेश

सहयोग राशि: 12 रु

संवाद हेतु संपर्क सूत्र:

ई-8/29, सहकार नगर
भोपाल 462039 मध्य प्रदेश

ईमेल:

dakhal.kishorebharati@gmail.com

फोन: 0755-2560438

9752907299

कहां क्या है:

कथनी:

सवालों की उंगली उठानी जरूरी है पृष्ठ 1 पर

करनी:

अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच—

दास्तान—ए—दखलंदाजी पृष्ठ 2 पर

शिक्षा अधिकार मंच, भोपाल: बुलंद बोलों

की यात्रा पृष्ठ 4 पर

गौरतलब है कि

कर्नाटक की कारगुजारी पृष्ठ 5 पर

नजरिया

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान: हवाई

महल बनाता एक और जुमला पृष्ठ 6 पर

विकलांगों की शिक्षा: एक और छलावा

पृष्ठ 7 पर

दृष्टि

पृष्ठ 8 पर

परख

पृष्ठ 12 पर

जन परिक्षेत्र से टोक

पृष्ठ 13 पर

खोज—बीन

पृष्ठ 14 पर

पड़ताल

मेडिकल शिक्षा का निजीकरण

पृष्ठ 17 पर

आईना: सोनम झा

पृष्ठ 18 पर

सवालों की उंगली उठानी जरूरी है

“अमीरी-गरीबी के बीच बढ़ती खाई एक जंजाल के रूप में खतरा है। इस स्थिति में सबसे बुरे अपराध को भी निर्दोष वाली दृष्टि से देखा जाना चाहिये। हमारे पास बहुत कम समय है। शायद इतना कम कि मैं खुद भी अनुमान नहीं लगा सकता।” सी.पी. स्नो

“भारत की शिक्षा व्यवस्था सड़क पर पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी आकर लात मारकर चला जाता है।” श्रीलाल शुक्ल, ‘रागदरबारी में’

साथियों, जब 27 जनवरी 2010 को इण्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों द्वारा स्वआलोचना का समाचार पड़ा तो क्षोभ की गहराइयां और बढ़ गईं। देश के शीर्षस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों का कहना था कि हम भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण जैसे आकर्षक मंत्रों के अनुयायी बनने के चक्कर में आम आदमी के प्रति सहानुभूति को खो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जी. एस. सिंघवी एवं ए.के. गांगुली ने कहा कि यदि हम तथाकथित भूमंडलीकरण के चलनों को प्रोत्साहित करने के चक्कर में यूं ही सांविधानिक जिम्मेदारियों को पनियल बनाते रहे तब देश को इसके घातक परिणामों के लिये तैयार रहना होगा।

जी हां, उच्चतम न्यायालय के इन न्यायाधीशों ने ठीक कहा था। लेकिन क्षोभ का विषय यह है कि, नवउदारीकरण जैसे छलावे के नाम पर किये जा रहे दमन को देखते रहने के बावजूद भी उच्चतम न्यायालय से एक मात्र स्वआलोचना की प्रतिक्रिया। हमारी शिक्षा व्यवस्था से लेकर, स्वास्थ्य एवं खाने-पीने की वस्तुयें चंद लोगों के फायदे का हिस्सा बन

चुकी हैं फिर भी न्याय मौन क्यों है? अभी हाल ही में देश भर में एक बड़े व्यवसाय के रूप में खुले हुये डीम्ड विश्वविद्यालयों में से कुछ विश्वविद्यालयों पर सरकार ने शिकंजा कसते हुये; उनका यह दर्जा रद्द करने का फैसला किया। साथियों, इन विश्वविद्यालयों में मध्यम वर्ग एवं उच्च मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों की पीढ़ी; नवउदारवादी अर्थव्यवस्था के बाजार के लिये तैयार की जा रही है। ये लोग लाखों रुपये देकर इन विश्वविद्यालयों की असुविधाओं के बावजूद धन के रूतबे पर शिक्षा को खरीदते हैं। इसीलिये इन विश्वविद्यालयों का दर्जा रद्द होने पर देश भर में हो हल्ला मचा पड़ा है। मीडिया से लेकर राजनेता तक कोई विकल्प निकालने को लेकर चिल्लपों करने में जुटे हुये हैं। उच्चतम न्यायालय में भी इस संबंध में याचिका दायर की गई। इसके बरक्स; नव वर्ष की पूर्वसंध्या पर कर्नाटक सरकार के द्वारा 500 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के फैसले को लेकर इन सारे ओहदों से एक आवाज भी नहीं सुनाई दी। इसके पहले भी इंदौर, दिल्ली, अहमदाबाद एवं चेन्नई में इस तरह की ज्यादातियों के खिलाफ इन हुक्मरानों में से किसी ने चिंता करने की जहमत नहीं उठाई। क्या सारे देश के लोगों के लिये इन हुक्मरानों एवं ओहदे वाले लोगों की जिम्मेदारियां परत दर परत

विभाजित हैं? कारण साफ है; क्योंकि उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का संबंध उस जनसंख्या से था जिसको असमानता के गर्त में लगातार दंश दिया जा रहा है।

अभी हाल ही में समाचार पत्रों में हमारी शिक्षा के रणनीतिकारों ने दो महत्वपूर्ण सुझाव सुझाये। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, सैम पित्रोदा ने विदेशी मेधाओं को आकर्षित करने के लिये भारी-भरकम फंडिंग की बात कही और दूसरा प्रस्ताव था सर्वशिक्षा अभियान को बंद करने का। बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चशिक्षा तक को पंगु बना देने वाले इन

रणनीतिकारों की मंशा हमें समझ में क्यों नहीं आ रही है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यशपाल कमेटी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन इन सारी रणनीतिक जिम्मेदारियों के जरिये शिक्षा के क्षेत्र में नवउदारवादी लालच के जाल को फलने-फूलने का मौका देना प्रस्तावित है। ज्यादा स्वायत्तता, सार्वजनिक निजी भागीदारी, सरकारी शिथिल व्यवस्था का अहस्तक्षेप; ये सारे जुमले केवल निजी फायदे की नीतियों को और पोढ़ा बनाने के लिये गढ़े गये हैं। इनके जरिये भारत में अलग-अलग वर्ग के लिये बहुपरती शिक्षा व्यवस्था लागू करने का एक भयानक जाल तैयार किया जा रहा है। आखिर इन सब नीतियों में सरकार की जिम्मेदारी कम करने को लेकर इतनी आतुरता क्यों है? 1966 के कोठारी आयोग की पड़ोसी स्कूल पर आधारित समान शिक्षा प्रणाली के सुझाव की पूरी उपेक्षा करने के बाद अब तक सरकार की प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में चल रही सारी योजनायें असफल रहीं। इन सारी योजनाओं में विश्व बैंक के इशारे पर शिक्षा की खुराक के तौर पर महज खानापूर्ति की गयी एवं पूरी व्यवस्था में असमानता का जहर घोला गया। इस तरह की असफलता के बावजूद सरकार की जवाबदेही कहां सुनिश्चित है?



कथनी

विश्व बैंक जैसी संस्थायें अपनी नीतियों के माध्यम से हमको निर्भर बनाने के लिये कमर कसे बैठी हैं। पहले प्राथमिक शिक्षा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी., 1990) के जरिये प्रारंभिक स्तर की शिक्षा को दीमक लगायी गयी और अब विश्व बैंक ने हमारी माध्यमिक शिक्षा के लिये भी इसी तरह की गोटियां फैलायी हैं। आखिर हम क्यों अपने नागरिकों की जरूरत संबंधी आवाजों को लतियाते हुये विश्व बैंक जैसी नवउदारवाद की पोषक संस्थाओं पर निर्भर बनने को आतुर हैं? शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में काफी दिनों से पैसे की कमी संबंधी अड़चनों को गिनाया जाता है। इसीलिए इसमें जोर-शोर से सार्वजनिक निजी भागीदारी की आवाभगत चल रही है। परंतु दूसरी तरफ राष्ट्रमंडल खेल एवं पार्कों की सुरक्षा जैसे भौंडे एवं शानो-शौकत के प्रदर्शनों पर करोड़ों रुपये बहाये जा रहे हैं। क्या ये दिखावटी नक्काशी भविष्य की इमारत की नींव को सुधारने से ज्यादा महत्वपूर्ण है ?

जुलाई 2009 में असमान शिक्षा प्रणाली के पोषाण आहार के तौर पर विकसित किये गये 'शिक्षा का अधिकार कानून' को पासकर सरकार ने अपने कार्यकाल में तमगा जड़ लिया। इस विधेयक से जुड़े महत्वपूर्ण बौद्धिक लोगों ने इसके खिलाफ उठने वाली आवाजों की खिल्ली उड़ाते हुये इसकी खूब वाह-वाही की। लेकिन क्या वे असमानता की शिक्षा व्यवस्था के कारण उत्पन्न मनोवैज्ञानिक परिणामों की अनदेखी नहीं कर

रहे थे? जी हां, हमने पूरे इतिहास में सामंतवाद, जातिवाद, वर्गवाद जैसी बुराइयां देखी हैं, जिनके परिणाम चीख-चीख कर कहते हैं कि ये भविष्य के लिए कितनी घातक हैं। आज शिक्षा में भी केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय, मॉडल स्कूल एवं उच्च शिक्षा की बहुपरती शिक्षा नीति के जरिये एक और असमानता की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके पीछे की मंशा नवउदारवाद रूपी लालच के जाल को बढ़ावा देना है। हमारे ही सामने हमारे सांविधानिक अधिकारों से मुंह मोड़कर हमारी सजगता की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। जातिवाद, अल्पसंख्यकवाद के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं ने भी इस असमानता की व्यवस्था को अपने संज्ञान में लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि इससे सीधे तौर पर उनके फायदे जुड़े हैं। हाल ही में डीम्ड विश्वविद्यालयों के रद्द दर्जों की सूची में से 16 विश्वविद्यालय राजनेताओं के थे। तब आखिर ये क्यों इस जाल से बाहर आयेंगे? लेकिन एक बात तो साफ है कि इस सारे क्रम में पूरे तौर पर आम-आदमीवाद को धता बताई जा रही है।

ये दखल उसी आम आदमी को चेताने की दिशा में एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि किसी भी पक्ष को अपनी पैनी चेतना से गुजारे बिना स्वीकार न किया जाये। जब आप ये प्रक्रिया अपनायेंगे तो खुद-ब-खुद निजी फायदे के मंसूबों को समझकर इस दखलंदाजी में शामिल हो जायेंगे।

अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच:

दारता-ए-दखलंदाजी

"केन्द्र सरकार अफरातफरी में बिना किसी लोकतांत्रिक लहजे का पालन करते हुये इस बिल को पारित करने जा रही है। इसके पीछे सरकार के तीन मतांध मन्तव्यों की पहचान की जा सकती है"

- :-
1. संविधान में वर्णित समानता पर आधारित शिक्षा प्रदान करने की बाध्यता से अपने हाथ खींचना।
 2. तथाकथित संभ्रांत तबके के स्कूलों (केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के 6000 मॉडल स्कूल) के अलावा पूरी सरकारी शिक्षा के ढांचे को तहस-नहस कर देना।
 3. स्कूली शिक्षा को निजीकरण एवं व्यापारीकरण के गर्त में धकेलने की गति को और तेज करना।

दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में नवउदारवादी ताकतों के बढ़ते हस्तक्षेप एवं सरकार से इसे मिलती शह को देखते हुये 21-22 जून 2009 को उस्मानिया विश्वविद्यालय कैम्पस हैदराबाद से अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच की यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। देश भर में शिक्षा पर हो रहे नवउदारवादी हमलों के प्रबल विरोध के लिये एक मंच से हुंकार भरने की दिशा में उठाये गये इस कदम के जरिये सबसे पहले 'शिक्षा अधिकार विधेयक-2008' की कलई खोली गई। हैदराबाद घोषणा पत्र के आधार पर भारत के राष्ट्रपति को इस विधेयक की तिकड़म से अवगत कराते हुये एक ज्ञापन भेजा

करनी

गया। इसका लब्बोलुआब कुछ इस प्रकार था :- "हम काफी समय से केन्द्र सरकार से अर्जी लगा रहे हैं कि-

1. 'शिक्षा का अधिकार विधेयक-2008' की जगह एक बिल के जरिये संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आधार मूल्यों की तर्ज से प्रेरित पड़ोसी स्कूल पर आधारित समान स्कूल व्यवस्था को स्थापित किया जाये।
2. संविधान के 86वें संशोधन (2002) का पनुरीक्षण कर इसमें बच्चों के लिये मौलिक आधार के तौर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा से 18 वर्ष की आयु तक

समानता
3. मौलिक
स्कूली व
सुदृढ़ ब
4. बिल
जरिये शि
हस्तक्षेप
को प्रति
गोया
व्यापारीक
द्वारा स्कू
वाउचर स
5. नये बिल
पूरी तरह
पारदर्शी
आयोजन
4 अगस्त
द्वारा सारे
को धता
अधिकार
कर दि
भारतीय
लोकतांत्रि
लेते हुये
को भेजे
संसद मा
ज्ञापन प्रे
में अवाज
उत्पन्न अ
के तरीके
26 अगस्त
बिल एक
दृष्टिगत
निम्नलिखि
1. उच्च
समिति क
2. स्कूली
संसाधन
3. राष्ट्रीय
मंत्रालय
शिक्षा के
नवउदारव
पर लगात

समानता पर आधारित शिक्षा को सुनिश्चित किया जाये।

3. मौलिक अधिकार की मूल भावना को तरजीह देते हुये पूरी स्कूली व्यवस्था के लिये वित्तीय मदद की सुनिश्चितता को सुदृढ़ बनाया जाये।

4. बिल में एक प्रावधान के जरिये शिक्षा के क्षेत्र में निजी हस्तक्षेप की सारी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाये। गोया कि— निजीकरण, व्यापारीकरण, निजी संस्थाओं द्वारा स्कूलों को गोद लेना, वाउचर स्कूल।

5. नये बिल के लिये पूरे देश में पूरी तरह से लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी सार्वजनिक विमर्शों का आयोजन किया जाये।

4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा सारे लोकतांत्रिक प्रयासों को धता बताते हुये 'शिक्षा का अधिकार विधेयक-2008' पास कर दिया गया। अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच ने

लोकतांत्रिक आवाजों के इस क्रूरतापूर्ण दमन को संज्ञान में लेते हुये जंतर-मंतर, दिल्ली पर इकट्ठा होकर राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले ज्ञापन के पक्ष में एक स्वर से हामी भरी। संसद मार्ग पर एक रैली निकालते हुये राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अलोकतांत्रिक कदम के विरोध में अवाज बुलंद करने के क्रम में संसद थाने की पुलिस द्वारा उत्पन्न अवरोध को खारिज करते हुये मंच ने महात्मा गांधी के तरीके को अपनाकर बिल की प्रतियां जलायीं।

26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होकर यह बिल एक कानून बन गया। इस संदर्भ में इस बिल को दृष्टिगत करते हुये मंच ने पूरी शिक्षा व्यवस्था में हो रहे निम्नलिखित नवउदारवादी हमलों को संज्ञान में लिया :-

1. उच्च शिक्षा के कायाकल्प एवं नवीकरण के लिये यशपाल समिति की रपट
2. स्कूली शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी-मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की एक विचारवादी सोच
3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा के क्षेत्र में विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी नवउदारवाद को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं के इशारों पर लगातार निजी फायदे की अर्थनीति को तरजीह दी जा

रही है। विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधारवादी ढकोसले के कदम के रूप में आयोजित जोमेतियन सम्मेलन के बाद से इस लालच के जाल को और तेजी से बढ़ाया गया।

इन सारे मन्तव्यों को विश्लेषित कर अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच पूरी तरह से अपनी मांगों को लेकर देश भर में आंदोलन को गति देने में लगा है। हमारी मांगों में साफ तौर पर स्पष्ट है :-

सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में संविधान की मूल भावना से इतर उठाये गये हर कदम के विरोध में देश भर में जनमत तैयार किया जायेगा और इसमें किसी भी तरह के समझौतावादी दृष्टिकोण का कतई स्वागत नहीं किया जायेगा। साथ ही संविधान में पुनरीक्षण के जरिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में

मजबूत करने की दिशा में और प्रयास किये जायेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र से सरकार द्वारा वित्तीय मदद से मुंह मोड़ने की हर कोशिश को चिन्हित कर इसके विरोध में जोरदार आवाज उठायी जायेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह की व्यापारिक मंशाओं की पहचान कर उनको इस व्यवस्था से बाहर करवाने की दिशा में मंच सदैव तत्पर है।

उच्च शिक्षा में स्वायत्तता एवं स्वच्छंदता के नाम पर नवउदारवादी एजेण्डे को बढ़ावा देने वाले प्रयासों के स्वागत एवं अनुमोदन को मंच सिरे से खारिज करता है।

हम इस मंच के जरिये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाने को तत्पर हैं जिसका लहजा एवं जिसकी तर्ज किसी शक्तिशाली वर्ग के चुनिन्दा लोगों द्वारा न तय की गई हो बल्कि इसमें वास्तविक रूप से सार्वजनिकता एवं जनता के लहजे की खुशबू हो।

आपका अपना

अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच
306, प्लिजेन्ट अपार्टमेन्ट्स, बाजारघाट

हैदाराबाद-4

फोन न. 04023305266

शिक्षा अधिकार मंच, भोपाल: बुलंद बोलों की यात्रा

साथियों,

'बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक, 2008' के ढकोसले के पीछे छिपी संविधान विरोधी, शिक्षा विरोधी, बाल विरोधी एवं निजीकरण-बाजारीकरण की तस्वीर साफ करने की दिशा में भोपाल में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। 27 जनवरी 2009 को 'शिक्षा अधिकार मंच, भोपाल' ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय संसदीय समिति को अपना विरोध पत्र

भेजकर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवउदारवादी हमलों के खिलाफ अलख जगाने की गति को तेज किया। इस पत्र का लब्बोलुआब कुछ ऐसा था -

"हमें आपको और आपके जरिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय संसदीय समिति के सभी सदस्यों को अत्यंत क्षोभ से सूचित करना पड़ रहा है कि उपरोक्त विधेयक की जड़ें भारत के संविधान में होने के बजाए वैश्वीकरण के तहत चलाई जा रही नवउदारवादी नीतियों के खाके में हैं। यह विधेयक संविधान की प्रस्तावना के समाजवाद, समानता एवं सामाजिक न्याय के संकल्प और अनुच्छेद 14, 15(1) व 16 में दिए गए क्रमशः कानून के समक्ष बराबरी राज्य के भेदभावपूर्ण रवैये से संरक्षण एवं सार्वजनिक रोजगारों हेतु समान अवसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि यह विधेयक पारित हो गया तो देश में बहुपरती (मल्टी लेयर्ड) स्कूल व्यवस्था और घटिया गुणवत्ता की शिक्षा का वैधानीकरण हो जाएगा। इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था का नकारात्मक असर मुख्यतः दलित, आदिवासी, अतिपिछड़े और अल्पसंख्यक बच्चों पर पड़ेगा खासतौर से इन समुदायों की लड़कियों व विकलांगों पर।

शिक्षा अधिकार मंच, भोपाल का औपचारिक गठन 14 फरवरी

2009 को भोपाल स्थित गांधी भवन में एक जनसभा के दौरान किया गया। इस जनसभा में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने 'बच्चों के लिये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक, 2008' के विरोध का संकल्प लिया। साथ ही भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवउदारवाद रूपी लालच के जाल से प्रेरित सभी प्रयासों के खिलाफ कदम उठाने के लिये हामी भरी गयी। इसके बाद से लगातार शिक्षा अधिकार मंच, भोपाल ने समानता पर आधारित शिक्षा प्रणाली को वास्तविक तरीके से कार्यरूप देने के लिये कसर कस ली। साथियों इस क्रम में पत्र प्रेषण के जरिये असमानता पर आधारित 'शिक्षा अधिकार विधेयक' के मन्तव्यों से मंच की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के स्पीकर को अवगत कराया गया।

राज्यसभा में महज 54 सांसदों की उपस्थिति में इस बिल के बिना किसी विरोध के पास हो जाने की लोकतांत्रिक लापरवाही को उजागर कर मंच ने इसके लिये बैठक बुलाकर विरोध दर्ज कराया। शिक्षा अधिकार मंच, भोपाल ने 9 अगस्त 2009 को भोपाल स्थित गांधी भवन में देश भर से शिक्षा अधिकार विधेयक' रूपी अलोकतांत्रिक कदम की विरोधी आवाजों का आह्वान किया। इस क्रम में हजारों की संख्या में आदिवासी, मजदूर एवं मत-निर्माताओं ने मंच की आवाज को बुलंदी दी। इस तरह शिक्षा अधिकार मंच, भोपाल शिक्षा के क्षेत्र में फायदे की व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले सारे कदमों के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहा है। साथियों हमने सारे दिखावटी जुमलों के बदले एक तर्ज संप्रेषित की है 'सबको शिक्षा एक समान, मांग रहा है हिन्दुस्तान'।

साथियों, पूरे देश में फायदे की अर्थव्यवस्था के जरिये शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे सारे नवउदारवादी प्रयासों (जैसे - ज्ञान आयोग, यशपाल कमेटी, विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक, मॉडल स्कूल, बहुपरती शिक्षा व्यवस्था) के विरोध में बजट सत्र के दौरान 24 फरवरी 2010 को अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। अपेक्षा है कि हमारी लड़ाई के लब्बोलुआब को समझकर आप इस रैली में हमें अपने कदमों का साथ देंगे एवं अलोकतांत्रिकता के विरुद्ध हमारी दखलअंदाजी को और मजबूत बनायेंगे।

आपका अपना

शिक्षा अधिकार मंच, भोपाल

ई-8/29, सहकार नगर, भोपाल 462039

मध्यप्रदेश

फोन न. (0755) 2560438

मो. 9752778439

ई-मेल:-shikshaadhikarmanch.bhopal@gmail.com

संवाद पत्र 1

'दरवाजा', फरवरी, 2010

कर्नाटक की कारगुजारी

साथियों,

बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकारें जिस तरह से लालच के पूरे जाल को पोढ़ा बनाने में जुटी हुई हैं उसमें भविष्य की एक बहुत बड़ी साजिश की बू आती है। जब हम वर्ष 2010 में अपनी खुशियां मनाने के लिये कमर कस रहे थे। सरकारें एवं समाचार पत्र पिछले साल की उपलब्धियों की एक लम्बी-चौड़ी सूची बनाने में लिप्त थे। उसी नववर्ष की पूर्वसंध्या पर कर्नाटक सरकार द्वारा 500 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद किये जाने के फैसले से प्रभावित लोगों की कचोट तमाम उपलब्धियों के मुंह पर एक कालिख की तरह थी। यह जरूर है कि कर्नाटक सरकार को इस कालिख का जरा भी एहसास नहीं हुआ और उसने बड़ी ही बेशर्मी से इन स्कूलों को बंद करने का कारण इनमें विद्यार्थियों की घटती संख्या बताया। क्योंकि बहुत हद तक स्पष्ट है कि कर्नाटक सरकार ने पहले से कुछ प्रदेशों में घट चुके अतीत को दुहराया था। यह कदम भी उन्हीं कारगुजारियों का एक हिस्सा था, जिसके जरिये प्राथमिक शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप एवं जिम्मेदारी को कमजोर बनाकर निजी निवेशकों के आगमन की संभावनाओं को बलवती किया जा रहा है। इस तरह की नीति 1999 में पहली बार मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनाई गई थी। इंदौर में 30 सरकारी स्कूलों को ठीक इसी तरह की धता बताकर बंद कर दिया गया था। बाद में इन स्कूलों की जगह पर तथाकथित आधुनिकता के महल शॉपिंग मॉल्स एवं सुरक्षा के दिखावे के आलय पुलिस थाने खोल दिये गये। (शायद सरकार को यह पहले से एहसास था कि हो सकता है इन स्कूलों को बंद करने से कुछ बच्चे अपराधी बन जायें तो उनको नियंत्रित करने के लिये थाने खोल दिये जायें।) ठीक इसी तरह की नीतियां बाद में दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई एवं चेन्नई में अपनाई गईं।

शिक्षाविद् डॉ. अनिल सद्गोपाल ने अपने एक शोध पत्र में इस कारस्तानी का हवाला कुछ इस प्रकार दिया—(मूल अंग्रजी से अनुवादित)

2004 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार निकला— “विद्यार्थियों की कमी को देखते हुये, शिक्षा निदेशालय ने 53 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, इसमें से ज्यादातर स्कूल पुरानी दिल्ली के हैं। ये 53 स्कूल उन 55 स्कूलों के अलावा हैं जो कि पहले ही बंद किये जा चुके हैं। हम लगातार सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या को महसूस कर रहे हैं।”

हिन्दुस्तान टाइम्स, 8 सितम्बर 2004

इन स्कूलों के बंद होने पर बिना किसी अफसोस के एवं स्कूलों की

व्यवस्था को सुधारने की सोच के बजाय एक उत्सवधर्मी वक्तव्य जारी किया गया, जो इस प्रकार था—

“इन स्कूलों के बंद होने से निदेशालय को दो तरह से सहायता मिलेगी। एक तो इन स्कूलों के अध्यापकों को कम अध्यापकों वाले स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जायेगा दूसरी ओर इन पर होने वाले खर्च की बचत होगी।”

दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है। क्यों न सरकार इन सारे स्कूलों को बंद कर दे और सारा का सारा खर्च बचाये।

(सद्गोपाल अनिल 2006, शोध पत्र— डाइल्यूशन, डिस्टार्टन एण्ड डाइवर्जन : ए पोस्ट जोमेतियन रिफ्लेक्शन ऑन एजूकेशन पॉलिसी, ‘द क्राइसिस ऑफ एलीमेन्टरी एजूकेशन’ (संपादक — रवी कुमार, सेज पब्लिकेशन्स, 2006 पृष्ठ संख्या 92-136)

दोस्तों, इन सारे कदमों में एक पूरे जाल की छवि उभरती है। क्योंकि शहर की अच्छी जगहों पर स्थित इन स्कूलों की जमीन पर लगातार लालची ताकतों की निगाह रही थी और कई जगह यह देखा गया कि

गौरतलब है कि

स्कूल बंद होने के बाद वह जमीन किसी निजी व्यवसाय के लिये सौंप दी गई। प्रश्न उठता है कि क्या ये व्यवसायिक हित उन बच्चों के भविष्य से ज्यादा बड़े थे? शिक्षाविद् डॉ. अनिल सद्गोपाल ने कर्नाटक सरकार के

स्कूलों को बंद करने के कदम एवं उसके लिये बताये गए कारणों पर कुछ सवाल उठाये। आइये देखते हैं इन सवालों को —

सवाल 1. हमारे यहां बहुत से पुलिस थाने ऐसे हैं जिसमें कभी-कभार ही कोई व्यक्ति रपट दर्ज कराने के लिये जाता है ? तब क्या इन थानों को बंद कर दिया जाता है?

सवाल 2. युद्ध के दिनों के अलावा सेना के खर्चों का बोझ इस आधार पर ज्यादा बढ़ा है। क्या सरकार इस मानक पर सेना के खर्चों में कटौती करती है?

तब फिर इन स्कूलों में बच्चों के न जाने की वास्तविक समस्या से मुंह फेरने जैसा यह लापरवाह कदम क्यों? आखिर क्यों सरकारें निजीकरण की टेक के सहारे हमारी शिक्षा व्यवस्था में असमानता का जहर घोलने के लिये इतनी आतुर हैं?

साथियों, कर्नाटक की कारगुजारी अपनी तरह की पिछली कारगुजारियों की तरह ही भयानक है। जरूरत है सरकारों के इस तरह के फैसलों को अपनी पैनी नजरों से गुजारकर एक हुंकार भरने की ताकि हमारी चीजें हमारे लहजे में रहें और हमसे ही छीनी न जायें।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः हवाई महल बनाता एक और जुमला

आंध्रप्रदेश शिक्षा बचाओ समिति के रमेश पटनायक ने माध्यमिक शिक्षा को वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धापूर्ण बनाने एवं इसके लोकव्यापीकरण की संभावनाओं की दृष्टि से सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र का अध्ययन किया। श्री पटनायक ने बारीक विश्लेषण के जरिये इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को चिन्हित किया। उनके विश्लेषण के अनुसार इसमें शुरु में सकारात्मक दिखने वाले पक्षों को जब सूक्ष्म स्तर पर परखा जायेगा तब वे भी सार्वजनिक निजी भागीदारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा देते नजर आयेंगे। रमेश पटनायक द्वारा किये गये विश्लेषण के कुछ प्रमुख अंश इस प्रकार हैं (मूल अंग्रेजी से अनुवादित)

सरकार ने अपने इस प्रपत्र में स्पष्ट किया है कि इस पूरे मिशन में नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक निजी क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करना जरूरी है। इस कार्यक्रम के अनुसार समान स्कूल प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य वहन करने योग्य फीस के बदले अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। राज्य को सार्वजनिक स्कूलों की व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र को (जैसे कि- भवन, सुविधाओं) में निवेश करना चाहिये जैसा कि केन्द्रीय विद्यालयों में किया जाता है। यह तथ्य अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है कि केवल आठवीं तक की शिक्षा किसी बच्चे को एक प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाने में असमर्थ है; साथ ही इससे बच्चा काम करने लायक भी नहीं बन सकता। हालांकि अनिवार्य रूप से माध्यमिक शिक्षा की सुनिश्चितता संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, फिर भी इसके महत्व को देखते हुये इसमें सहभागी भूमिका अदा करने की जरूरत है। लेकिन इसी समय 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ड्रॉपआउट रेट (कक्षा 1 से 5 तक 28.49 प्रतिशत एवं कक्षा 1 से 8 तक 50.39 प्रतिशत) को देखते हुये माध्यमिक स्तर पर पूरी तरह से शिक्षा का लोकव्यापीकरण मुमकिन नहीं दिखता। फिर भी माध्यमिक स्तर पर शिक्षा तक पहुंच की सुलभता से कक्षा 1 से 8 तक स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति काबू में आयेगी। इस योजना की दृष्टि में 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं 2020 तक पूरी तौर पर स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को काबू करने की बात रखी गयी है। इस पूरी योजना में माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिये सोच में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है। इस बदली सोच में सर्वसुलभ

पहुंच, समानता, सामाजिक न्याय, प्रासंगिक पाठ्यक्रम एवं ढांचागत पहलुओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा। इस तरह के मूल्यों को माध्यमिक शिक्षा में लाने के लिये गैर-अनुदानित निजी स्कूलों की भूमिका को भी रेखांकित किया जायेगा ताकि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को भी इन स्कूलों में स्थान मिल सके। इस पूरे कार्यक्रम में सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये नये स्कूल भी खोले जाएंगे। साथ ही गैर सरकारी संस्थाओं को भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रखा जायेगा। मसलन गांवों में लड़कियों के लिये छात्रावास बनवाना। इस कार्यक्रम में कमजोर तबके के लिये पढ़ते

नजरिया

समय रोजगार उपलब्ध कराने की संभावना को भी तलाशा गया है ताकि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस पूरे कार्यक्रम में भवन की जरूरतों से लेकर खेल के मैदान तक सामुदायिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी इन स्कूलों को आवश्यक सुविधाओं से लैस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

राज्य सरकार पाठ्य पुस्तकें, कार्यपुस्तकें, स्टेशनरी जैसे महत्वपूर्ण स्रोतों की सुविधायें मुहैया करा सकती है। इस प्रपत्र में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का जिक्र करते समय ड्रॉपआउट के कारणों का पता लगाने संबंधी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। शिक्षा पर किये जा रहे भारी-भरकम खर्च के बावजूद ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निचले मध्यम वर्ग और गरीब तबके के व्यस्क जीविका जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिये शिक्षा से वंचित हैं। इसलिये ऐसे बिन्दुओं को रेखांकित कर एक वैकल्पिक माध्यमिक शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा किया जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाएँ बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दे रही हैं। इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थाओं की भूमिका को और मजबूत किया जायेगा। मसलन क्षमता वृद्धि, सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा, मूल्यांकन एवं निगेहबानी में इनकी भूमिका को बढ़ाकर। निजी स्कूलों में सॉफ्टवेयर के जरिये गरीब तबके के नामांकन को सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही साथ सरकारी जिम्मेदारी को कम करते हुये सामुदायिक भागीदारी के जरिये स्कूलों को विकसित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जायेगा। निजी क्षेत्र के भागीदारों को अपने फायदे के हिस्से को लोकहित के कार्यों में लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही निजी क्षेत्र की प्रबंधन में भूमिका को और मजबूत किया जायेगा एवं पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जायेगा। मॉनीटरिंग के लिये गैर सरकारी संस्थाओं का एक पैनल तैयार किया जायेगा।

टिप्पणी: इस पूरे विश्लेषण को देखते हुये जो सरकारी मंशा जाहिर होती है वह यह है कि सरकार अपने सुधारवादी लबादे के जरिये एक और कार्यक्रम का जाल बिछाने जा रही है। इस कार्यक्रम में विकास के सुधारवादी एजेन्डे के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किये जायेंगे। लेकिन सरकार, पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी कम करने एवं निजी फायदे की संभावनाओं की गोटी को इस योजना के जरिये फिट बैठायें जाने की कवायद जारी रखेगी। इस पूरे कार्यक्रम के जरिये हमारी व्यवस्था के चमकीले पहलू को तो थोड़ी चमक अवश्य मिलेगी; लेकिन इससे फायदे के संजाल में पिस रही कमजोर आवाजों को कोई मजबूती नहीं मिलेगी। निजी क्षेत्र को आंख मूंदकर शिक्षा व्यवस्था की बागडोर सौंपने एवं गैर सरकारी संस्थाओं के फायदे वाले मंसूबों को जानते हुये भी उनकी भूमिका को मजबूत करना एक विनाशक कदम है। इससे केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा एक उत्पाद बनकर रह जायेगी।

विकलांगों की शिक्षा: एक और छलावा

अनिवार्य शिक्षा विधेयक में संशोधन की मंजूरी; अधिक विकलांग बच्चों को मिल सकेगा लाभ, बढ़ाया जाएगा परिभाषा का दायरा। अब किसी भी तरह की विकलांगता से ग्रस्त बच्चों को पास के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आरक्षण मिल सकेगा। इसके लिए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने गुरुवार को बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून 2009 में संशोधन के लिये विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे अगले सत्र में संसद में रखा जाएगा। संशोधन के जरिए विकलांगता की परिभाषा के दायरे को व्यापक बनाया गया है। जिससे सभी तरह के विकलांग बच्चों को कानून के प्रावधानों का लाभ मिल सके।

दैनिक भास्कर, 25 दिसम्बर 2009, भोपाल

विकलांग बच्चों की योजना के बारे में अफसरों ने मुख्यमंत्री से बोला झूठ भीम सिंह मीणा, भोपाल
मध्यप्रदेश में करीब दो हजार विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा दिलाने वाली इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम (आईईडीसीएस) की राज्य स्तरीय सेल का गठन अब तक नहीं हो पाया है। केन्द्र सरकार ने 18 साल पहले इस योजना को शुरू करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे।

मंत्री बदलते रहे और योजना आगे बढ़ती रही
8 साल में योजना चली महज दो कदम

दैनिक भास्कर/डीबी स्टार, 19 जनवरी 2010, भोपाल

ऊपर के समाचारों के अंशों से स्पष्ट है कि विकलांगों की शिक्षा को लेकर व्यवस्था ने जिस तरह से उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है, वह बेहद चिंताजनक है। इस पूरे क्रम को हम दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस

मेरी कॉलेज की व्याख्याता अनिता घई के नजरिये से देखते हुये और गूढ़ता से समझ सकते हैं (मूल अंग्रेजी से अनुवादित)– समाज में काफी हद तक विकलांगता को एक निजी स्वास्थ्य से जुड़े पहलू के रूप में देखा जाता है। निजीकरण के फैलते जाल एवं नागरिक को एक उपभोक्ता के रूप में विकसित करने के क्रम के फलस्वरूप सरकार की भूमिका सार्वजनिक रूप से काफी कमजोर हो चुकी है। पूरे भारत में

5-14 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 30 लाख विकलांग बच्चे हैं। स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में विकलांगता के पहलू को पूरी तरह से नकारा गया है। जहां तक मेरा मानना है लगभग 90 प्रतिशत

विकलांग बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधा मुहैया नहीं हो पाती। सरकार द्वारा विकलांगों की शिक्षा को दो मंत्रालयों के बीच खींचतान के लिये छोड़ देने से विकलांगों की शिक्षा को और भी हाशिए पर ढकेला जा रहा है। (सामान्य शिक्षा के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विशेष शिक्षा के लिये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय)। सर्व शिक्षा अभियान एवं पिछली अन्य



योजनाओं में विकलांगों की शिक्षा को दी जाने वाली तरजीह में साफ तौर से उन्हें शिक्षित बनाने वाले पहलू को नकारा गया है। इन सभी में महज अनौपचारिक रूप से साक्षर बनाने पर बल दिया गया है। 2001

जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत की कुल साक्षर जनसंख्या 65 प्रतिशत की तुलना में विकलांगों की साक्षरता का आंकड़ा मात्र 49 प्रतिशत है। तथाकथित शिक्षा का अधिकार देने वाले विधेयक में अनुच्छेद 2(डी) जोड़कर इसे विकलांगों के लिये समावेशी बनाने के कर्तव्य से इतिश्री कर ली गई। लेकिन इसमें 0-6 एवं 14-18 साल तक के विकलांग बच्चों के लिये कोई प्रावधान न कर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों को पूरी तरह से नकारा गया। पूरी शिक्षा व्यवस्था की योजनाओं के क्रम

में विकलांगों के लिये महज जुमलों वाली नीतियों के जरिये छलावा किया गया है और नवउदारवादी ताकतों के मनमाने रवैये से संचालित नयी योजनाओं में भी यह जारी है।

‘काबिले गौर है कि: “वेनेजुएला में राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मानते हुये एक कार्यक्रम चलाया। इसमें स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका को सुनिश्चित कर एक अभियान के जरिये स्कूल से बाहर लोगों को स्कूलों में वापस लौटाने की कवायद की गई। इस पूरे कार्यक्रम की वित्तीय मदद राष्ट्रीय नीति के जरिये की जाती थी एवं इसमें सीधी जवाबदेही राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के प्रति सुनिश्चित थी।”

टिप्पणी: यह आवश्यक नहीं है कि हम वेनेजुएला के कार्यक्रम की नकल करें। लेकिन हम इससे यह सीख सकते हैं कि हमारी सरकार में इच्छाशक्ति की कमी का स्तर क्या है? आखिर क्यों हमारी व्यवस्था में जवाबदेही को लेकर इतना संशयवादी दृष्टिकोण है? जवाबदेही एवं इच्छाशक्ति के नाम पर हमारी व्यवस्था का संचालन करने वाले अनमने क्यों हो जाते हैं?

दृष्टि

साथियों, वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में फायदे का जाल बिछाने के मद्देनजर जिस तरह से प्रयास जारी हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। सत्ता में बैठे लोग, पूंजीपति एवं बुद्धिजीवी नवउदारवाद के नाम पर जनता से छलावा करने में लीन हैं। इसको समझने के लिये हमने पिछले कुछ दिनों के समाचार पत्रों से इस तरह के समाचारों एवं लेखों के अंश निकाले जिनमें इस पूरी साजिश की बू थी। आइये करते हैं एक मुआयना:-

कटघरे में : दोस्तों, सत्ता वर्ग के लोग अपनी करतूतों को हमेशा जूमिंग लेंस से दिखाने में मशगूल रहते हैं। लेकिन इन समाचारों के विश्लेषण से साफ है कि इन सारी असफलताओं को समझकर यदि सत्ता वर्ग का पर्दाफाश किया जाये तो इनका मकसद अपनी तिकड़मों से शिक्षा को एक फायदे का धंधा बनाना है :-

इंतजामों की बाट जोहता पुरवा मीना मेनन

मरडी (महाराष्ट्र) का जिक्र करते हुये उन्होंने लिखा कि किस तरह पारधी बाहुल्य पुरवा के लिये श्रीपुर गांव में कक्षा चार तक के लिये एक स्कूल है। पुरवा गांव से 2 किमी. दूर स्थित है। जबकि गांव से पुरवा तक जाने के लिये कोई रोड भी नहीं है। यहां अध्यापक अपनी मर्जी अनुसार आता है। यहां पर आंगनवाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये यहां के ज्यादातर बच्चे स्कूल छोड़कर खेतों में काम करने लग जाते हैं।

द हिन्दू, 27 दिसम्बर 2009, नई दिल्ली
(मूल अंग्रेजी से अनुवादित)

मापदंडों पर खरा नहीं उतरने का आरोप, 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों की मान्यता खतरे में: केन्द्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बातया कि वह जनहित में 44 संस्थाओं का डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लेने जा रही है। इन संस्थानों के पास डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा बरकरार रखने के लिए जरूरी क्षमता नहीं है। ऐसे विश्वविद्यालय 13 राज्यों में फैले हैं।

दैनिक भास्कर, 10 जनवरी 2010, भोपाल

वरना चीनी बच्चों से पीछे रह जाएंगे हम: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के प्रति सरकार को अपना नजरिया बदलने की सलाह देते हुए कहा कि हमारे यहां 14 साल से छोटे सभी बच्चों को अनिवार्य

और मुफ्त शिक्षा देने की बात की जाती है, लेकिन यह सिर्फ कागजों पर होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात सरकारी स्कूलों में टीचरों के 6,000 खाली पड़े पदों के बारे में हलफनामा दाखिल करने वाले गुपीएससी और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को निर्देश देते हुए कही।

नवदुनिया, 15 जनवरी 2010, भोपाल

सपना न बन जाये अनिवार्य शिक्षा मोहिनी माथुर

यदि सरकार बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के प्रति गंभीर है तो उसे अपने साधनों का उपयोग ऐसा ढांचा बनाने में करना चाहिए कि अधिकांश बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही अच्छी शिक्षा मिल सके। क्या कारण है कि अकूत पैसा लगाने के बावजूद आज तक सरकारी स्कूल विद्यार्थियों की पहली परसंद नहीं हैं?

नवदुनिया, 15 जनवरी 2010, भोपाल

एक छोटी सी बात: केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने देशभर में चल रहे करीब चार लाख एक शिक्षक वाले स्कूलों की प्रासंगिकता पर उचित ही सवाल उठाया है। हमारी सरकारों की प्राथमिकता में शिक्षा शुरू से ही हाशिए पर रही है। अब देर से ही सही, ऐसे स्कूलों को बहुशिक्षक बनाया जाता है; तो उससे न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, बल्कि लाखों की संख्या में नए रोजगार भी सृजित होंगे।

दैनिक भास्कर, 6 अक्टूबर 2009, भोपाल

दृष्टि

असमानता का जहर: साथियों, इन समाचरो को विश्लेषित कर हम समझेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में तरह-तरह के सजावटी दिखने वाले कदमों को उठाकर किस तरह से असमानता का जहर समाज में घोला जा रहा है:

कोर्ट ने संस्कृति स्कूल के प्रबंधन को लगाई फटकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले छात्रों से भेदभाव करने के संदर्भ में संस्कृति स्कूल के प्रबंधन की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि आप स्कूल के नाम पर कोई दान नहीं कर रहे। यह स्कूल जनता के पैसे से चलता है। ये भेदभाव किस आधार पर किया जा रहा है?

द हिन्दू, 17 दिसम्बर 2009
(मूल अंग्रेजी से अनुवादित)

लाखों की लैब में नहीं उपकरण: राज्य सरकारों का बालिका शिक्षा व बालिका उत्थान का दावा खोखला नजर आ रहा है। राजधानी के कई स्कूल अब भी कम्प्यूटर व प्रैक्टिकल लैब में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा लाखों रुपये खर्च कर पिछले सत्र में लैब का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन अब तक लैब में पर्याप्त संसाधन नहीं उपलब्ध कराए गए। उपकरण न होने की वजह से दसवीं कक्षा की 17 एवं 9वीं कक्षा की 60 छात्राओं को प्रैक्टिकल करने संकुल केन्द्र जाना पड़ता है।

दैनिक भास्कर, 11 दिसम्बर 2009, भोपाल

पठन-पाठन में सुधार की सरकारी कोशिशें ढाक के तीन पात: शासन जनपद के परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं के पठन-पाठन में सुधार के लिए लाख प्रयास कर रहा है। इसके लिए बच्चों की जानकारियों के मानक भी तय कर दिए गए हैं लेकिन इससे इन विद्यालयों के विद्यार्थियों में सुधार नहीं आ पा रहा है। इसका असर न ही विद्यार्थियों के बौद्धिक ज्ञान पर पड़ा है और न अध्यापक ही इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के प्रति गंभीर हुए हैं।

इस बारे में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामशंकर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन का स्तर सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार स्कूलों की सघन चेकिंग लगातार की जा रही है। इसमें बच्चों की उपस्थिति, मिड-डे मील के साथ ही बच्चों के पठन-पाठन में सुधार के लिए भी अध्यापकों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है।

जनसत्ता, 22 दिसम्बर 2009,

हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों का नतीजा यह है कि पिछले एक-डेढ़ दशक में कोचिंग ने स्वतंत्र उद्योग की शकल ले ली है। आज यह 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का उद्योग बन चुका है। 8-10 कोचिंग संस्थाओं ने बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का रूप ले लिया है, जिनका व्यवसाय प्रतिवर्ष 20 फीसदी की दर से बढ़ रहा है कोचिंग का यह व्यवसाय देश के लगभग 75 शहरों में फैला है, जिनमें से ज्यादातर मंझोले और छोटे दर्जे के शहर हैं। कैंट और आई.आई.टी. जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए ही कोचिंग उद्योग 1500 करोड़ रुपये का हो चुका है। बेहतर रोजगार की बढ़ती भूख के साथ इसमें माता-पिता की महत्वाकांक्षाओं का भी बहुत जबरदस्त योगदान है।

दैनिक भास्कर 6 जनवरी 2010

टिप्पणी: पैसे के बल पर कुछ लोग तो इस कोचिंग जैसी व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। उनको भी इसमें लूटा ही जाता है। लेकिन उस वर्ग के सांविधानिक अधिकारों का तो मजाक ही उड़ रहा है, जो पैसे की कमी के चलते सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर है।

सैटेलाइट शालाओं को लेकर

जिलों की बेरुखी: राज्य शिक्षा केन्द्र ने दो माह पहले ही श्योपुर में 9, उज्जैन, राजगढ़ व विदिशा में 6-6 सैटेलाइट शालाओं के संचालन की स्वीकृति दी थी, लेकिन इनमें से राजगढ़ को छोड़ कहीं भी ये शालाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। समीक्षा बैठक में इसका खुलासा हुआ। अभी तक के विश्लेषण से पता चला है कि 48 शालाएं शुरू ही नहीं हुई हैं। इस घोर लापरवाही से शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं।

नवदुनिया 16 दिसम्बर 2009 (भोपाल)

नई सोच ब्लागस्पॉट डॉट कॉम उमेश पंत

सरकारी स्कूलों के लिए सरकार की उपेक्षा को दूसरे चश्मे से देखें तो ऐसा होने की वजह साफ दिखाई देती है। निजी स्कूल यानी मोटा पैसा। और कई शिक्षा माफियाओं के कमीशन सरकारी अफसरों की झोली में।

खुद सरकार में बैठे नेताओं के कितने पब्लिक स्कूल दिल्ली में चल रहे हैं, यह बात किसी से नहीं छिपी है। इसलिए ऐसे हालात पैदा करना जरूरी है जिससे सरकारी स्कूल लोगों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के अंतिम विकल्प भी बने रहें। मौजूदा हालात देखकर सरकार की यह मंशा साफ हो रही है।

जनसत्ता, 9 जनवरी 2010, नई दिल्ली

इच्छा शक्ति की कमी:

मित्रों सरकारें दिन-ब-दिन अपने द्वारा किये जा रहे प्रयासों को बहुत ज्यादा बताती हैं। मगर व्यवस्था की खराबी को वे स्वीकारती नहीं, बल्कि एक नये अलोकतांत्रिक मकसद से अपनी छवि को निखारने का काम करना चाहती हैं। इन समाचरो में हम पाएंगे कि किस तरह संविधान एवं मानवीय मूल्यों के इतर सत्ता पक्ष ने अपनी इच्छाशक्ति को लकवाग्रस्त बनाया है —

दृष्टि

सरकारी मसूबे: दोस्तों, हर बार किसी योजना में गड़बड़ी होने का कारण सरकारी ढांचे में क्रमवार शिथिलता एवं जटिल प्रक्रिया को बताया जाता है एवं इसके जरिए शिक्षा में निजी हस्ताक्षेप एवं उसकी स्वायत्तता की वकालत की जाती है। लेकिन अगर इन समाचारों की परख हम अपनी पैनी दृष्टि से करेंगे तो पायेंगे कि सत्ता वर्ग के इस स्याह पक्ष के पीछे की पूरी मंशा ही इस तरह की स्थिति बनाकर लालच के जाल को और मजबूत बनाना है:

मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल पहले ही कह चुके हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में लाना उनके मंत्रालय की प्राथमिकता है। मंत्री जी की इच्छानुसार कैबिनेट के सामने विदेशी विद्यालय बिल पहले से प्रस्तावित है। बिल में विदेशी विश्वविद्यालयों को डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा देने की बात कही गयी है। (मूल अंग्रेजी से अनुवादित)

ईडीयू ट्रेक अक्टूबर 2009

विनीता पांडे/भास्कर/डीएनए विशेष: सिब्बल के दावों की हवा निकली; अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने कहा भारत को लेकर कोई योजना नहीं।

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने हाल ही में अमेरिका से लौटने पर बड़े-बड़े दावे किए थे। उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालयों की लंबी सूची पढ़कर कहा था कि ये सभी देश में कैम्पस स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि, उसी सूची के दो विश्वविद्यालयों ने भास्कर/डीएनए को पत्र लिखकर भारत आने की योजना से साफ इंकार किया है। सिब्बल के दावों के विपरीत न तो हार्वर्ड विवि यहां आने का इच्छुक है और न ही जार्ज वाशिंगटन विवि।

दैनिक भास्कर, 4 जनवरी 2010, भोपाल

बुरा सपना बन गई बोगस यूनिवर्सिटीज

एजेंट्स विदेश में पढ़ाई के नाम पर ले लेते हैं पैसा और वहां हकीकत होती है एकदम अलग: इंग्लैण्ड में बेहतरीन पढ़ाई और बढ़िया करियर का सपना देखने वाले छात्रों को वहां पहुंचकर कई परेशानियां उठानी पड़ रही हैं; क्योंकि इनमें से कई यूनिवर्सिटीज बोगस हैं। भारत में इनके एजेंट सक्रिय रहते हैं जो छात्रों को बेहतर भविष्य की बात कहकर उनसे पैसा वसूल लेते हैं लेकिन जब ये छात्र यूके पहुंचते हैं तो उन्हें सड़कों पर सोने और भूखे रहने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

वैसे खुद ब्रिटिश सरकार भी इन बोगस यूनिवर्सिटीज से चिंतित है और चार सौ ऐसे संस्थानों को बंद करने के बाद अब 800 पर नजर रखे हुए है, लेकिन ठगे जा रहे छात्रों के लिये इंतजाम नहीं हो पा रहा है।

दैनिक भास्कर/डीबी स्टार, 15 दिसम्बर 2009

संपादकीय: भारतीय शिक्षा सेवा

मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा आदि की तरह ही भारतीय शिक्षा सेवा गठित करने का विचार लेकर सामने आए हैं।

नवदुनिया, 23 दिसम्बर 2009, भोपाल

मान्यता का संकट अभी बरकरार

मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की मान्यता बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की कछुआ चाल के चलते संकट और गहराता जा रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बताई गई कमियां 70 से 80 फीसदी जस की तस हैं। अभी भी मेडिकल कॉलेजों में 30 से 40 फीसदी पद खाली हैं। एमसीआई पहले ही प्रदेश के पांचों मेडिकल कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा कर चुकी है।

नवदुनिया, 29 दिसम्बर 2009, भोपाल

देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य केन्द्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की बेहतरी के नाम पर वेलियाथन समिति की जिस रपट को लागू करवाने में प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है; दरअसल यह रिपोर्ट ही गैर लोकतांत्रिक है।

वेलियाथन ने संस्थान में समूह तीन व चार की भर्ती निजी क्षेत्र से आउटसोर्सिंग आधार पर करने की बात कही है। लेकिन एक अन्य सदस्य पी.के. होता ने इससे असहमति जताते हुए कहा है कि यह भर्ती कर्मचारी चयन समिति की ओर से की जानी चाहिए। वेलियाथन ने संस्थान की ओर से निजी क्षेत्र को परामर्श देने का रास्ता खोलने की वकालत की है जबकि पी.के. होता ने एम्स के दूसरे सरकारी शिक्षण व अन्य संस्थानों से तालमेल की दरकार बताई है।

जनसत्ता, 15 दिसम्बर 2009, नई दिल्ली

“देश में 23,000 शोधार्थियों की जरूरत”

सिब्बल ने कहा है कि पूरी दुनिया में शिक्षा का विकास उद्योग जगत ने किया है। अमेरिका व ब्रिटेन के नामी विवि वहां के व्यापारियों ने बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब पैसे नहीं हैं कि वह शिक्षा में पूंजीनिवेश करे। इसलिए उद्योग जगत को आगे आना होगा। उन्होंने कहा भारत में शिक्षा में दाखिले का प्रतिशत 12.4 प्रतिशत है जो विश्व के औसत प्रतिशत से 38 प्रतिशत कम है। उन्होंने कहा कि 19 करोड़ 40 लाख बच्चे अभी भी कॉलेज नहीं जा पाते। उच्च शिक्षा में 30 प्रतिशत दाखिले का लक्ष्य चाहिए तो चार करोड़ छात्रों के लिए और कॉलेज खोलने होंगे लेकिन यह सरकार के बलबूते पर संभव नहीं। व्यापारी वर्ग, सरकार तथा शिक्षाविदों को अब एक मंच पर आना होगा। नवदुनिया, 12 जनवरी 2010, भोपाल

टिप्पणी: सरकार के बलबूते राष्ट्रमंडल खेल के नाम पर करोड़ों रुपये बहाना संभव है। और क्या व्यापारी विश्वविद्यालयों का निर्माण मुनाफे की संभावना के बिना करेंगे? शिक्षा को व्यापारियों के हाथ देकर बिकने की वस्तु बनाना कहाँ तक सही है ?

दृष्टि

निजी शिक्षा का चरित्र:

साथियों, जिन निजी निवेशकों एवं भागीदारों के बलबूते पर हम शिक्षा जगत की पींगों को ऊँचाई पर पहुंचाने की बात करते हैं, इन समाचारों के जरिये हमें इन निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों का फायदे एवं केवल फायदे के लिये काम करने का रूप नजर आयेगा। जैसे तो हम स्वायत्तता के नाम पर निजी निवेशकों के द्वारा किये जा रहे खिलवाड़ को देखते ही हैं, लेकिन ये समाचार हमारी सोच को और पुख्ता बनाते हुए बतायेंगे कि यह पूरा जाल ही इनके फायदे के लिये बुना गया है।

गरीब छात्रों का हक मार रहे उच्च शिक्षण संस्थान

नवनीश कुमार (सहारनपुर)
सरकार के नए कालेज न खोलने, वर्तमान कालेजों की उपलब्ध सीटों को भी लगातार घटाते जाने और गरीब छात्रों को निजी क्षेत्र के हवाले करने से सरकार खुद उच्च शिक्षा से मुंह चुरा रही लगती है। बी.एड कराने वाला दून कालेज गुणवत्ता की पोषक शैक्षिक परिषदों व आयोगों के निर्धारित मानकों को ताक पर रख हर साल उपलब्ध सीटों से ज्यादा दाखिले कर लेता है। फिर परीक्षा न दिला पाने पर उनकी फीस वापस करने या दूसरे प्रदेशों से डिग्री दिलाने के झांसे देता है।

जनसत्ता 22 जनवरी 2010

"मनमानी पर लगेगा अंकुश":

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने निजी तकनीकी कॉलेजों को एक बार फिर मनमानी करने से वंचित कर दिया है। मौजूदा प्रवेशित छात्रों की ब्रांच अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में छात्रों से मनमानी राशि लेकर ब्रांच अपग्रेड करने की शिकायतें दूर करने के लिए आरजीपीवी ने वेबसाइट पर सभी छात्रों की मेरिट सूची डालने का फैसला किया है।

दैनिक भास्कर, 11 दिसम्बर 2009, भोपाल

वर्चस्व की पाठशाला

दुनिया मेरे आगे (अरमान)

लेकिन सामंती, अभिजात शक्तियों ने अपने विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिये तरह-तरह के जाल बुने हैं। मसलन देसी भाषाओं की जगह अंग्रेजी भाषा में शिक्षा और कामकाज, सामान्य सरकारी स्कूलों की जगह विशेष सरकारी स्कूलों और अब मॉडल स्कूलों को देखा जा सकता है। अभिजात वर्ग अपने बच्चों के लिए मंहगे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की श्रृंखला खुलवाने में जुटा है।

कोठारी आयोग ने कहा था, यह शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि विभिन्न सामाजिक तबकों और समूहों को एकत्र करे और इस प्रकार समतामूलक और एकजुट समाज को विकसित होने को प्रोत्साहित करे। लेकिन आज शिक्षा खुद सामाजिक भेदभाव और वर्गों के बीच फासला बढ़ा रही है। यह स्थिति गैर-लोकतांत्रिक है और समतामूलक समाज से मेल नहीं खाती।

शिक्षा में निजीकरण और व्यवसायीकरण पर कोई रोक नहीं है। खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा में निजी भागीदारी और पूंजीनिवेश को बढ़ावा देने, निजी-सरकारी सहयोग, विदेशी शिक्षण संस्थानों को प्रवेश देने जैसे कदम उठाए हैं। ये प्रावधान सबको शिक्षा, समान शिक्षा के उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

जनसत्ता 21 अक्टूबर 2009

शिक्षा की दुकान (संपादकीय) : राजधानी और उससे सटे

उपनगरों के स्कूल दाखिले और फीस के मामले में मनमानी से बाज नहीं आ रहे। स्कूलों की मनमानी पर अभिभावकों की नाराजगी को देखते हुए उच्च न्यायालय ने कई बार शिक्षा मंत्रालय को खरी-खोटी सुनाई, कुछ निर्देश जारी किए गए पर उन्हें अनसुना कर दिया गया। निजी स्कूलों को बाजार दर से काफी कम कीमत पर इस शर्त के साथ भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं कि वे कमजोर तबके के बच्चों के लिए दाखिले में पच्चीस फीसदी सीटें आरक्षित रखेंगे। लेकिन कई बार अदालत की फटकार के बावजूद ज्यादातर स्कूल इस शर्त का पालन नहीं करते। जो स्कूल नियम-कायदों को मानने का दिखावा भी करते हैं तो बड़ी हुई रकम वसूलने के दूसरे रास्ते निकाल लेते हैं। स्कूलों की जिम्मेदारी पाठ्यक्रम के अनुरूप विद्यार्थियों को प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल के मैदान जैसी सुविधाएं और पढाई-लिखाई का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने की होती है। मगर अक्सर उनका जोर पाठ्येतर गतिविधियों पर अधिक देखा जाता है। वातानुकूलित बसें और कक्षाएं, तरणताल, आधुनिक सुविधाओं वाले सभागार और खेल परिसर, घुड़सवारी, शैक्षिक यात्रा के नाम पर बच्चों को विदेश भेजने, निजी कंपनी की प्रतियोगिताएं और तरह-तरह के मेले आयोजित करने जैसे दिखावे करते रहते हैं। निजी स्कूलों में पैसा कमाने की होड़ प्रबल होती गई है। दरअसल, सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत और समान शिक्षा व्यवस्था कायम कर पाने में सरकारों की नाकामी के चलते निजी स्कूलों की शरण लेना लोगों की विवशता होती गई है।

जनसत्ता, 25 दिसम्बर 2009, नई दिल्ली

पर्चे कठिन आने से फेल हुए: 66 फीसदी छात्र

आरजीपीवी के बीई सेकेंड सेमेस्टर में विद्यार्थियों के खराब प्रदर्शन पर निजी कॉलेजों ने दिया तर्क। निजी कॉलेजों की एसोसिएशन ने आरजीपीवी से छात्रों के स्तर के अनुसार परीक्षा लेने का अनुरोध किया है।

दैनिक भास्कर, 4 दिसम्बर 2009, भोपाल

परख

बयान दर्ज: मनमोहन सिंह (मूल अंग्रेजी से अनुवादित)

केन्द्र सरकार भारत को विश्वभर में उच्चशिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्रों में शुमार करने के लिये क्रांतिकारी कदम उठा रही है। उच्चशिक्षा से जुड़े शिक्षण संस्थानों को एक ढर्रे से हटकर रद्दी के समान विद्यार्थी तैयार करने के बजाय कौशल, बुद्धिमत्ता एवं तथ्यपरकता से जुड़े विद्यार्थी तैयार करने की जरूरत है। इसके लिये इन संस्थानों को और स्वतंत्रता एवं सुलभता दी जायेगी।

द हिन्दू, 4 जनवरी 2010

चपत: जी हां, तभी स्वायत्तता का हवाला देकर कमेटियों के मशविरे से ऐसी गोटियां बिछायी जा रही हैं कि जिससे पैसे वाले ही पढ़ पायें और पैसे वाले उससे पैसे कमायें। ये विदेशी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय तो रद्दी को और बढ़ाते हैं। महोदय आपने भी तो पंजाब विश्वविद्यालय से शिक्षा ली है। तब निजीकरण की इतनी आवाहगत क्यों?

बयान दर्ज: कपिल सिब्बल (मूल अंग्रेजी से अनुवादित)

इस समय विद्यार्थियों पर जबरदस्त दबाव है। हम इसको लेकर चिन्तित हैं। इसके घातक परिणाम भी सामने आते हैं, लेकिन हम किसी एक मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

द हिन्दू, 8 जनवरी 2010

चपत: सिब्बल साहब बच्चों पर ये दबाव तो निजी स्कूलों के पैसाकमाऊ चरित्र और उनके सजावटी पैमानों में स्वयं को फिट बैठाने को लेकर है। और उनके दबाव का क्या जिनके लिये शिक्षा का अधिकार कानून

पास कराकर आपने घोर असमानता की खाई खोदी है या वे जो बहुपरती शिक्षा व्यवस्था का शिकार हैं?

बयान दर्ज: शीला दीक्षित (मूल अंग्रेजी से अनुवादित)

सरकारी स्कूलों ने पब्लिक स्कूलों की चमक को फीकी कर दिया है। अभिभावक अब सरकारी स्कूलों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं।

द हिन्दू, जनवरी, 2010

चपत: जी मैडम, ध्यान दीजिए सरकारी स्कूल भी बंटे हुए हैं। बड़े लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय, कुछ के लिए नवोदय। उनका क्या जिनको 2004 में सरकार पर बोझ बताकर बंद कर दिया गया था? वो भी सरकारी विद्यालय ही थे। जब अभिभावक तरजीह दे रहे हैं तो फिर सरकारी शिक्षा में समानता एवं बेहतरी की उपेक्षा क्यों?

बयान दर्ज: मनमोहन सिंह (मूल अंग्रेजी से अनुवादित)

हमारे शैक्षिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की जरूरत है। शैक्षिक प्रयासों को पटरी पर लाने में ये हमारे लिये सबसे बड़ी चुनौती है।

द हिन्दू, 12 नवम्बर 2009

चपत: महोदय तभी बड़ी-बड़ी कंपनियों के मैनेजर गोलमेज बैठकों के जरिए हमारी शिक्षा व्यवस्था का रोडमैप तैयार कर रहे हैं। शिक्षक तो तभी बेहतर बनेंगे जब शिक्षा बेहतर बनेगी और मुनाफे को शिक्षा से जोड़कर ये संभव नहीं है।

सफलताओं एवं असफलताओं से सीख पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षा की परख करने वाला रिपोर्ट कार्ड:

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षा पर बनी प्रतीची ट्रस्ट की रिपोर्ट को जारी करते हुये कई अनुशासकों से रूबरू करवाया। श्री सेन ने कहा कि हमारे अध्ययन के मुताबिक कई जगह प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सुधार हुआ है लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है—

शिक्षकों की अनुपस्थिति पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।

मिड डे मील योजना को और सशक्त बनाने की जरूरत है।

पालकों एवं शिक्षकों के बीच एक बेहतर समझ के जरिये शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने की जरूरत है।

स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था को नये ढंग से बनाकर उसकी खामियों को दूर करने की आवश्यकता है।

पाठ्यक्रम के बोझ के चलते छात्रों की प्राइवेट ट्यूशन एवं कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता को नियंत्रित करने की जरूरत है। प्राइवेट ट्यूशन अमीर-गरीब के बीच बनी खाई को और चौड़ा करती है। शिक्षा व्यवस्था में फैली खामियों को किसी जादुई तरीके से दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि देश के लाखों लोगों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने की।

द हिन्दू, 19 दिसम्बर 2009

टिप्पणी: देश के एक जाने-माने अर्थशास्त्री द्वारा शिक्षा व्यवस्था का इस तरह विश्लेषण जंचता नहीं है। महोदय ये सारे सुधार तो उनके लिए हैं जिन्हें स्कूल नसीब हैं। इनमें से ट्यूशन और कोचिंग से संबंधित सुझाव तो एक निश्चित वर्ग के लिए हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो स्कूल जाने वाले आयु वर्ग में होते हुए भी बहुपरती शिक्षा व्यवस्था के कारण स्कूल से बाहर रहने को मजबूर हैं? उनमें से लगभग 5 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं। व्यवस्था का इस अंदाज में विश्लेषण; व्यवस्था को अपनी कमियां वैधानिक करने का मौका देता है।

विचार

सस्ती व सर्वसुलभ तकनीकी शिक्षा

भारत में तकनीकी शिक्षा इतनी मंहगी है कि विद्यार्थी योग्यता के बावजूद उसे पा नहीं सकते। शिक्षा सस्ती व सर्वसुलभ होनी चाहिए। उन्नत देश वही है जो सबको समाज शिक्षा का अवसर दे।

एन आर नारायण मूर्ति
इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक

लेख दैनिक भास्कर, 6 जनवरी, 2010

जन परिक्षेत्र से टोक

शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण के बढ़ते हस्तक्षेप के चलते दिनों-दिन बड़े शहरों में निजी शिक्षण संस्थाओं का जाल फैलता जा रहा है। ये संस्थायें बड़े-बड़े दावों के बल पर विद्यार्थियों को गुमराह करती हैं एवं बेहतर भविष्य की आस में बैठे विद्यार्थी लालच के जाल में फसते जाते हैं। भूमण्डलीकरण, नवउदारीकरण जैसे ख्याली ढकोसलों के नाम पर विद्यार्थियों से मुनाफे का धंधा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप लालच का एक पूरा क्रम चलता है। इस पूरी अव्यवस्था के गवाह हैं;

भोपाल के ये छात्र जिन्होंने अपनी समस्याओं के साथ-साथ निजी संस्थाओं की कारगुजारी का ब्यौरा हमें बतलाया।

इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नॉलजी में एम. एस. सी कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे खुमेन्द्र कावड़े का कहना है:

हमसे ट्यूशन फीस के अलावा किसी बाहर से विशेषज्ञ को बुलवाकर पढ़ाई करवाने के नाम पर अतिरिक्त पैसे लिये गये।

हमें छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

फीस में हर साल पैसा बढ़ा दिया जाता है; लेकिन उसके सापेक्ष सुविधाओं में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाती है, बल्कि उनमें दिनोंदिन गिरावट ही आती जाती है। लाइब्रेरी में किताबों की उपलब्धता की भी हालत काफी बदतर है। जो किताबें उपलब्ध भी हैं; वे केवल खानापूरी के लिये हैं।

दुब्रा इंजीनियरिंग कॉलेज एवं टेक्नोकेंट्रस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई करने वाले विवेक, पीयूष और गौरव का कहना

है -

हमको पढ़ाने वाले अध्यापक अनुभवी नहीं होते। जो इक्का-दुक्का अच्छे शिक्षक हैं भी वो धीरे-धीरे छोड़कर जा रहे हैं। तमाम नियमों को ताक पर रखकर हमें यहीं से बी.ई. (बैचलर इन इंजीनियरिंग) करके गये लोगों से पढ़वाया जाता है। इसीलिये हमको बाहर कोचिंग भी करनी पड़ती है। हमारे यहां पर्सनैलटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार एवं इंटरव्यू के लिये अलग से कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। जब हम अपने प्रबंधन से बात करते हैं तो वे हमें बाहर कोचिंग में पढ़ने की सलाह देते हैं।

ट्यूशन फीस के नाम पर राशि लेने के बाद भी तरह-तरह के अन्य खर्चों के नाम पर हमसे पैसे वसूले जाते हैं। मसलन विश्वविद्यालय विकास फीस, बस की फीस। बस फीस अनिवार्य है चाहे आप कॉलेज से कितनी भी दूरी पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी-बड़ी कंपनियों के कैम्पस प्लेसमेंट के नाम पर हमसे मोटी धनराशि वसूली गयी। जब कंपनियां कैम्पस सेलेक्शन के लिए आती हैं, तब बहुत कम लोग उनकी

योग्यता के दायरे में आ पाते हैं; क्योंकि पढ़ाई की स्थिति बहुत ही खराब रहती है।

कॉलेज वालों पर मुनाफे का भूत इस कदर हावी रहता है कि वे एक ही कॉलेज कैम्पस में चार-चार कॉलेज चलाते हैं। एक-एक कक्षा में 120 विद्यार्थी पढ़ते हैं।

व्यवहारिक ज्ञान (प्राैक्टिकल नॉलेज) से हमें कोसों दूर रखा जाता है। जिन प्रयोगशालाओं के बिना हमारे पाठ्यक्रम निरर्थक हैं, उनका कॉलेज में कोई नामोनिशान नहीं मिलता। मसलन-स्ट्रेन्गथ ऑफ मैटेरियल

लैब, थर्मोडाइनामिक्स की लैब, मैकेनिक्स की वर्कशॉप। कई बार कॉलेज वाले विश्वविद्यालय के नियमों की खानापूरी के लिए

अव्यवस्थित प्रयोगशालाएं देते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है। कम्प्यूटर साइंस की प्रयोगशाला में

कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की अनुपलब्धता रहती है। सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियां तो कॉलेज में कभी भी होती ही नहीं हैं। अगर कभी इसके लिये

कॉलेज प्रबंधन से बात करो तो वे कहते हैं कि आप लोग इंजीनियर हैं केवल

इंजीनियरिंग पढ़िये।

हम जब भी कॉलेज के गैर-लोकतांत्रिक फैसलों के विरोध में आवाज उठाते हैं तो हमें सेशनल के अंकों की धमकी दी जाती है। सेशनल के 500 अंकों के नाम पर हमें अपनी वाजिफ मांगों से वंचित किया जाता है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के बीच कोई तालमेल नहीं रहता। हम लोग लेटरल इंट्री से थे तब भी हमारी परीक्षाएँ मुख्य परीक्षाओं के साथ घोषित की गयीं, जब हम लोगों ने उनको उनके ही बनाये नियमों से अवगत कराया तब हमें तरह-तरह की दिक्कतों से

रुबरू होना पड़ा। साथियों निजी शिक्षण संस्थाओं की अंधाधुंध बढ़ती भीड़ का मुख्य मकसद केवल और केवल मुनाफा कमाना है। इन विद्यार्थियों की आपबीती साफ-साफ इशारा करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुनाफे के व्यवसाय का यह कीड़ा दिन-ब-दिन शिक्षा व्यवस्था को खोखला बना रहा है। इन विद्यार्थियों की आपबीती इस क्रम में एक टोक है जिसे हमें हुंकार में बदलना होगा।

हमें हुंकार में बदलना होगा।

हमें हुंकार में बदलना होगा।

हमें हुंकार में बदलना होगा।

हमें हुंकार में बदलना होगा।

खोज-बीन

साथियों, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे सारे प्रयास इशारा करते हैं कि सरकार दिनों-दिन इस क्षेत्र से अपनी जिम्मेदारी कम करने की फिराक में है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्वशिक्षा अभियान और अब शिक्षा का अधिकार। ये सारी योजनायें शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार की लकवाग्रस्त इच्छाशक्ति को दर्शाती हैं। असल में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में इतनी चूक नहीं हुई, जितनी कि इन योजनाओं को बनाने में की गई। ये सारी योजनायें ही इस विकल्प के तौर पर आयीं कि सभी योजनायें शिक्षा में सार्वजनिक व्यय की लचर हालत को दिखाकर, निजी सेवादाताओं के लिये मार्ग प्रशस्त करेंगी। ये सभी योजनायें एक असमान व्यवस्था की पोषक हैं। लेकिन हमारी सरकार निजी सेवादाताओं के लालची रूप पर पर्दा डालते हुये दिन पर दिन हमें बेहतर शिक्षा का ख्याली एहसास कराने के लिये कमर कस रही है। आइये इसकी बानगी देखते हैं इन दो समाचारों में:

अक्षय मुकुल,

‘शिक्षा में सुधार के लिये कॉरपोरेट जगत ने सुझाये तरीके’ कॉरपोरेट जगत के सदस्यों से शिक्षा से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विषयों पर नीति के लिये एक रोडमैप तैयार करने के सुझाव मांगे गये। ये क्षेत्र हैं— व्यवसायिक शिक्षा, शोध में सार्वजनिक निजी भागीदारी, गैर-अनुदानित स्कूलों में शिक्षा का खर्च कम करना। ये सारे सदस्य मानव संसाधन मंत्रालय की उच्च शिक्षा पर होने वाली गोलमेज बैठक के हिस्से थे। बैठक में निजी निवेश को शिक्षा के क्षेत्र में और फलदायी बनाने पर विचार आये। साथ ही साथ मेधावी छात्रों को गैर-अनुदानित निजी संस्थानों में सहायता दिलाने की बात पर विचार हुआ। बैठक में मानव संसाधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये वित्तीय निवेश के लक्षित क्षेत्रों की संभावनायें तलाशी गयीं एवं निवेश को और ज्यादा आकर्षित करने के लिये भी चर्चा हुई।
टीएनएन, 20 नवम्बर 2009 (मूल अंग्रेजी से अनुवादित)

सवाल उठते हैं: साथियों सवाल उठता है कि मैकाले की शिक्षा नीति की तरह ये आधुनिक मैकाले हमारी शिक्षा नीति में हस्तक्षेप करके मनमर्जी का मानव संसाधन तैयार करने के इच्छुक क्यों हैं? जी हाँ, मेरे अनुसार जवाब स्पष्ट है क्योंकि नवउदारवाद रूपी लालच के जाल का पूरा मकसद ही पूँजी द्वारा सारी चीजों को नियंत्रित करना है। नवउदारवाद दुबारा से एक शक्तिशाली वर्ग की सत्ता की चाहत पूरा करने का तरीका है। यह सोच जब व्यापार एवं अर्थशास्त्र की थी तब हमारी शिक्षा व्यवस्था पर ये हमला क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य बड़ी मात्रा में फायदे के दम पर एक वर्ग की सत्ता स्थापित करना है। इस सत्ता को स्थापित करने के लिये शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकृति लाना जरूरी है। जिन मेधावी लोगों की बात ये करते हैं वे मेधावी किस तरह से एवं किस स्तर पर बनते हैं? जी हाँ, हमारी बहुसंख्यक जनसंख्या के लिए नवउदारवादी ताकतों का नेतृत्व करने वाली विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के इशारे पर; शिक्षा की उपलब्धता की महज खानापूति की जा रही है। जिसमें मेधावी बनना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें तो केवल सांकेतिक साक्षर बनाकर पीठ थपथपाने का काम चल रहा है। क्या यहां पर उन मेधावियों की बात की जा रही है, जो मोटी रकम के बल पर रटने वाली पढ़ाई का हिस्सा बनते हैं? अगर ऐसा है तो उन लोगों का क्या, जिनकी मेधा को इस असमान शिक्षा व्यवस्था के चलते मेधा की दौड़ से बेदखल कर दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री ने सरकारी स्कूल व्यवस्था में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया: सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिये एक खुशी का समाचार है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एतिहासिक कदम उठाते हुये सरकारी स्कूल व्यवस्था में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रस्तावित किया है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे सुविधाओं से युक्त कक्षाओं में पढ़ेंगे साथ ही साथ मुफ्त वेशभूषा, मध्याह्न भोजन और मुफ्त किताबों की योजना को इसी व्यवस्था के अंतर्गत जारी रखा जायेगा। इसके जरिये केवल और केवल सरकार द्वारा की जाने वाली निगेहबानी को कम किया जायेगा। ऐसा माना जाता है कि निजी स्कूलों के अध्यापक सरकारी स्कूलों की अपेक्षाकृत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए कम आय वर्ग के लोग भी सरकारी स्कूलों की सांकेतिक फीस या मुफ्त शिक्षा के बदले थोड़ी ज्यादा फीस वाले निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने को तरजीह देते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानना है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने वित्तीय अड़चनों के चलते हाईस्कूल खोलने बंद कर दिये हैं।

साथ ही सरकार द्वारा स्कूलों के लिये भवन निर्माण, अध्यापकों की भर्ती एवं अध्यापकों के चयन में काफी समय खर्च होता है। निजी क्षेत्र में इन सारी दिक्कतों से निजात मिलेगी और काम में तेजी और व्यवसायिकता आयेगी। निजी क्षेत्र के हस्तक्षेप से इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी, जिससे कम व्यय में स्तर में सुधार आयेगा। सूत्रों के अनुसार ये स्कूल पूरी तरह से सरकारी स्कूल ही होंगे, बस इनमें ढांचागत निर्माण एवं बजट संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिये निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा। स्कूलों की शुरुआत हो जाने के बाद विद्यार्थियों पर होने वाले व्यय को सरकार द्वारा वित्तीय मदद के जरिये पूरा किया जायेगा। निजी क्षेत्र को अपने स्टॉफ की भर्ती, उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण एवं स्कूलों के सतह संचालन में पूरी स्वायत्तता दी जायेगी।

टाइम्स ऑफ इंडिया, 8 अक्टूबर 2009 (अंग्रेजी से अनुवादित)

सवाल उठते हैं: सत्तर के दशक में कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित पड़ोसी स्कूल पर आधारित समान स्कूल प्रणाली में सरकारी जिम्मेदारी को कम करने की नौबत क्यों आने दी गई? आज लोग सरकार की शिक्षा व्यवस्था में बहुपरती व्यवस्था होने के चलते अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं। और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा तो ऐसा

खोज-बीन

है जोकि निजी स्कूलों जैसे जुमले की कल्पना ही नहीं कर सकता। यह हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी लापरवाही के चलते बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय स्कूल छुड़वाने पर मजबूर हो जाता है। जिस स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता की बात यहां पर की जा रही है उसके भ्रष्ट रूप की एक झलक हम इन्हीं निजी खिलाड़ियों की विज्ञापन नीति में देख सकते हैं। विज्ञापन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक इन निजी खिलाड़ियों के बीच केवल और केवल प्रतिद्वंद्विता का विकृत रूप देखने को मिलता है। क्या इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था का भविष्य खतरे में नहीं पड़ेगा? (अनिल अंबानी बनाम मुकेश अंबानी, पेप्सी बनाम कोला)। जब सरकारें भोंडे प्रदर्शनों (राष्ट्रमंडल खेल, पार्क निर्माण) के लिये करोड़ों पैसे खर्च कर रही हैं तब शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट संबंधी अड़चनों की बात ही क्यों उठती है? ये तो साफ-साफ इशारा करता है कि ये प्रयास हमारे हितों को निजी निवेशकों के हाथ बेचने की साजिश हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी सरकार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से अपने हाथ खींचने को इतना आतुर क्यों है? ये प्रबंधन के उन बेसिर-पैर के सिद्धांतों को इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में लागू करने के लिये क्यों कुलबुला रही है, जोकि केवल और केवल लालच के पोषक हैं? आर्थिक मंदी, सत्यम, ऐनरॉन इन सारी घटनाओं से साफ जाहिर है कि प्रबंधन के आज के सिद्धांत केवल और केवल लालच के जाल को मजबूत करने के लिये बने हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मीडिया इस निजी भागीदारी की पींगों को इतना बढ़ा-चढ़ाकर क्यों दिखाती रहती है? जवाब बहुत साफ है कि फायदे की व्यवस्था में मीडिया को विज्ञापनों का बहुत बड़ा हिस्सा इन निजी क्षेत्रों से मिलता है तब इसकी खैरखाही करना जरूरी तो है ही।

इसी निजी स्कूली शिक्षा के विकृत रूप को हम इन समाचारों में देख सकते हैं:

मोटी राशि जमा करने के बावजूद नहीं मिल पाई मार्कशीट, फीस में उलझे सपने: भोपाल के एक निजी फैशन इस्टीट्यूट और उसके चंडीगढ़ स्थित हेड ऑफिस की खींचतान के कारण कुछ छात्रों की मार्कशीट उलझ कर रह गई है। चंडीगढ़ से फीस न जमा होने की बात कही जा रही है जबकि छात्र महीनों पहले भोपाल में पूरी फीस जमा कर चुके हैं।

अभिभावक की व्यथा

(शाशांक जैन), "बैंक से लोन लेकर बेटी के बेहतर भविष्य के लिये उसका एडमिशन आईएआईएफडी में करवाया था। समय पर फीस जमा की, लेकिन वे मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। बहाने सुनते-सुनते डेढ़ साल बीत गया है। बार-बार फोन लगाओ तो वे अपने भाई और पूर्व सांसद का नाम लेकर धमकाते हैं।"

"भोपाल चंडीगढ़ में उलझी मार्कशीट" छात्रों ने फैशन में कॅरियर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लेकर दी है इस्टीट्यूट को मोटी फीस, छात्रों की फीस में से लेते हैं कमीशन।

दैनिक भास्कर/डीबी स्टार, 13 दिसम्बर 2009, भोपाल

तीसरी बार फीस बढ़ाने पर बवाल: दिल्ली अभिभावक महासंघ अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने पब्लिक स्कूलों की ओर से साल भर में तीसरी बार फीस बढ़ाने पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में छठे वेतन आयोग के नाम पर विद्यालयों और सरकार की लीपापोती का मामला थमा भी नहीं था कि स्कूलों ने कानूनी दांवपेच के नाम पर फिर से फीस बढ़ाने का राग अलापना शुरू कर दिया है। इसलिए इस साल अप्रैल से फीस को फिर दुबारा 10 फीसदी बढ़ाने का कदम गैर कानूनी तो है ही शिक्षा के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। पब्लिक स्कूल एक साल में तीन बार फीस बढ़ोत्तरी, बस किराया बढ़ोत्तरी, दाखिले के नाम पर अंधाधुंध वसूली व अन्य मदों में लगातार पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं।

जनसत्ता, 17 जनवरी 2010, नई दिल्ली

तथ्य कुछ और फरमाएं नंबर पर न जाएं: लेख, यतीश राजावत छोटे-छोटे शहरों में कुकुरमुत्तों की तरह इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज उग आए हैं, लेकिन इनमें गुणवत्ता कहीं नजर नहीं आती। ये बड़ी संख्या में ऐसे स्नातकों की फौज पैदा कर रहे हैं, जिन्हें एक अदद नौकरी तक नहीं मिल पाती है। हमारे यहां 1,346 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें से अधिकांश पिछले एक दशक के दौरान अस्तित्व में आए। चाहे वह आइसक्रीम वाला हो या ज्वेलर, यदि उसके पास अतिरिक्त जमीन है तो उसने कॉलेज खोल लिया। वर्ष 2005 में मेरीट्रैक ने सभी मध्यम स्तरीय शहरों में इंजीनियरिंग प्रतिभा पर एक अध्ययन करवाया था। इसमें पता चला कि केवल 23 प्रतिशत छात्र ही ऐसे थे, जो कोई रोजगार पाने के लायक थे। देश भर के निजी संस्थानों का बिजनेस मॉडल दबाव में है। अधिकांश निवेश भूखंड और भवन पर खर्च हो जाता है और फैंकल्टी इत्यादि पर कोई व्यय नहीं किया जाता।

दैनिक भास्कर, 4 अक्टूबर 2009, भोपाल

साथियों विश्व भर में नवउदारवाद के रूप में चल रहे लालच के क्रम की झण्डाबरदारी वैश्विक स्तर पर बनायी गई कुछ तथाकथित आदर्शवादी संस्थाएं कर रही हैं। जिनकी नियमावली पुस्तकों में बड़े-बड़े आदर्शवादी लक्ष्यों को लिखा गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इन संस्थाओं के हर कदम पर पैनी चेतना से विचार करना। क्योंकि बड़े फायदे के जरिये पूंजी की शक्ति को कुछ लोगों के हाथ में सौंपने की व्यवस्था को फलने-फूलने देना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। इनमें से एक संस्था है विश्व बैंक, जोकि हर साल अपनी बौद्धिक तिकड़मों के जरिये भारत की विकास नीति में किसी न किसी तरह हस्तक्षेप करती है। जनवरी 2009 में विश्व बैंक ने भारत में द्वितीयक स्तर (माध्यमिक शिक्षा) की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं इसके सर्वव्यापीकरण की संभावनाओं को टटोलते हुये एक रिपोर्ट तैयार की। जिसमें प्राथमिक शिक्षा के बाद अब द्वितीयक स्तर की शिक्षा की महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करते हुये कुछ अनुशंसाएं की गई हैं। आइये अपनी आलोचनात्मक चेतना के माध्यम से इनका विश्लेषण करते हैं।

खोज-बीन

इसमें कहा गया है कि: भारत में प्राथमिक शिक्षा में सरकार की भूमिका काफी स्पष्ट है। पिछले दस सालों से प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, स्कूल न छोड़ने एवं एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने जैसे क्षेत्रों में असाधारण बदलाव आया है।

इससे द्वितीयक स्तर की शिक्षा व्यवस्था पर काफी दबाव बढ़ रहा है। नयी खेप की बढ़ती संख्या एवं द्वितीयक स्तर पर व्याप्त असमानता से सामना करना इस स्तर की प्रमुख प्राथमिकतायें होनी चाहियें। द्वितीयक स्तर की शिक्षा के बेहतरीकरण से भारत की अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि (ग्रोथ) को और तेज किया जा सकेगा। साथ ही साथ बढ़ते बाजार में मानव संसाधन एवं श्रम की जरूरत को भी पूरा किया जा सकेगा। हाल ही में शुरू किये गये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन में द्वितीयक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने की काफी संभावनायें हैं। इसमें गुणवत्ता, समानता, जवाबदेही एवं योग्यता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की संभावनाओं की झलक मिलती है।

(राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का आलोचनात्मक विश्लेषण देखें - नजरिया स्तंभ में रमेश पटनायक के विचारों में) इस पूरे प्रपत्र के जरिये विश्व बैंक के रणनीतिकारों ने कुछ अनुशंसाएं सुझायी हैं। आइये डालते हैं एक नजर :-

- 1) सार्वजनिक स्कूलों का निर्माण किया जाये।
- 2) नवाचार से युक्त सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल को लागू किया जाये।
- 3) दो शिफ्ट में अध्यापन को कार्यरूप दिया जाये।
- 4) मल्टीग्रेड अध्यापकों की भर्ती की जाये।
- 5) आंतरिक रूप से गुणवत्ता एवं दक्षता बढ़ाने के लिये कार्यक्रम चलाये जायें (ऐसा प्राथमिक शिक्षा में सर्वशिक्षा अभियान के जरिये किया जा रहा है।)
- 6) पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जाये एवं उसे नयी तरह से तैयार किया जाये।
- 7) भारत में बहुपरती प्रबंधित स्कूली व्यवस्था (केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अब मॉडल स्कूल) का इतिहास रहा है, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये और प्रयोगों और सुधारों की जरूरत है।
- 8) मांग पक्ष (डिमांड साइड) पर आधारित वित्तीय मदद को बढ़ाया जाये।

सवाल उठते हैं: साथियों, विश्व बैंक के इस पूरे प्रपत्र को पढ़ने के बाद साफ जाहिर होता है कि इसमें गरीबी हटाने के लिये द्वितीयक स्तर की शिक्षा में आमूलचूल बदलाव जैसे आदर्शवादी ढकोसले के पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। ये ठीक उसी तरह से है; जिस तरह से विश्व बैंक ने प्राथमिक शिक्षा में हस्तक्षेप करके हमारी प्राथमिक शिक्षा को कहीं का नहीं छोड़ा है।

मसलन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) एवं उसके जरिये

कई तरह के शिक्षक पैदा करना। जिस प्राथमिक शिक्षा के सुधरे रूप की बात इस रिपोर्ट में की गई है। असल में तो वह एकदम पंगु बनायी जा चुकी है, जिससे हमें उसे निजी निवेशकों के हाथों में सौंप देना पड़े। अभी हाल की एसइआर की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता के असली रूप को खोलती है। इसके अलावा मुझे मध्यप्रदेश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि पुनर्विलोकन में उपस्थित होने का मौका मिला।

इसमें शिक्षा पर आधारित सत्र में विश्व बैंक के इशारों पर चले जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर एकदम असफल बताया गया। जिन मल्टीग्रेड अध्यापकों की बात इसमें कही गयी है। मसलन टीचर, पैराटीचर, गुरुजी। ये कई तरह के अध्यापक शिक्षा के बेहतरीकरण में सबसे बड़ी बाधा बताये गये।

साथ ही साथ खुद योजना आयोग, मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि ने स्वीकारा कि केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर प्राथमिक शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाये। शिक्षा विकास सूचकांक में हमारी स्थिति काफी खराब है। सर्वशिक्षा अभियान को घसीटा जा रहा है। साफ जाहिर है कि क्या केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है?

ध्यान दें मन्तव्यों पर

वैश्विक बाजार का उपभोक्ता बनाने की साजिश शिक्षा में वर्गवाद को बढ़ावा देकर सांविधानिक मूल्यों को धता बताना।

निर्भरता की लत को पोढ़ बनाकर वैश्विक साहूकारी को मजबूत बनाना।

शिक्षा को एक उत्पाद (कमोडिटी) बनाकर इसमें मुनाफे के व्यवसाय के लिए मार्ग प्रशस्त करना।

संस्थाओं के पिछलगू बनकर केवल और केवल साक्षर भारत की मुहर लगवाना होना चाहिये?

विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में जिस मांग पक्ष (डिमांड साइड) पर आधारित वित्तीय मदद की बात की है, यह वित्तीय मदद का पूरा जाल हमें वैश्विक बाजार के लिये महज एक उपभोक्ता के रूप में विकसित करना है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था का पूरा उद्देश्य वैश्विक शक्तियों के इशारों पर नाचते हुये उनके बाजार के लिये एक उपभोक्ता बनना होना चाहिए? कुल मिलाकर यह पूरी रिपोर्ट हमारी शिक्षा व्यवस्था के एक और स्तर (द्वितीयक स्तर) पर नवउदारवाद रूपी दीमक लगाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इससे हमारी द्वितीयक स्तर की शिक्षा खोखली होगी और फिर हमें इसे निजी फायदे की व्यवस्था को सौंपने के लिये मजबूर किया जायेगा।

मेडिकल शिक्षा का निजीकरण

डॉक्टर एनडीटीवी (एक वेबसाइट) ने मेडिकल की पढ़ाई कराने वाले निजी (प्राइवेट) संस्थानों की बढ़ती संख्या के संबंध में एक सर्वे किया। इसमें मुख्य रूप से दक्षिण भारत के संस्थानों को शामिल किया गया था। सर्वे के आधार पर उत्तरदाता लोगों में से ज्यादातर लोगों का मानना है कि निजी संस्थानों की इस तरह भेड़ियाधसान से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के चयन में प्रतियोगिता का स्तर घटिया होता है। यह चयन मेरिट पर आधारित न होकर धन पर आधारित होता है और इससे अकादमिक गुणवत्ता भी घटती है। सर्वे में यह तथ्य सामने आया कि भारत में मेडिकल शिक्षा का निजीकरण चिकित्सकों के स्तर में गिरावट को प्रेरित करता है, साथ ही यह निम्न स्तर के चिकित्सकों का निर्माण करता है। ये चिकित्सक अपनी पढ़ाई में लगाई गयी मोटी रकम को अनैतिक तरीके से अपने मरीजों से वसूलने की आवश्यकता समझते हैं।

इस सर्वे में पूछे गये प्रश्न एवं उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उनके उत्तर इस प्रकार थे (अंग्रेजी से अनुवादित)

क्या प्राइवेट संस्थानों के फैलते जंजाल से

प्रश्न 1. अच्छे शिक्षकों की कमी होगी?

उत्तर - 72.70 प्रतिशत लोगों ने हां कहा।

21.40 प्रतिशत लोगों ने नहीं कहा।

5.90 प्रतिशत लोगों ने कहा कुछ नहीं कह सकते।

प्रश्न 2. विद्यार्थियों का चयन मेरिट की बजाय पैसे के आधार पर होता है?

उत्तर - 86.20 प्रतिशत लोगों ने हां कहा।

10.60 प्रतिशत लोगों ने नहीं कहा।

3.20 प्रतिशत लोगों ने कहा कुछ नहीं कह सकते।

प्रश्न 3. मेडिकल शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है?

उत्तर - 81.40 प्रतिशत लोगों ने हां कहा।

16.30 प्रतिशत लोगों ने नहीं कहा।

2.30 प्रतिशत लोगों ने कहा कुछ नहीं कह सकते।

प्रश्न 4. शिक्षा का स्तर घट रहा है ?

उत्तर - 74.40 प्रतिशत लोगों ने हां कहा।

19.70 प्रतिशत लोगों ने नहीं कहा।

5.80 प्रतिशत लोगों ने कहा कुछ नहीं कह सकते।

प्रश्न 5. क्या इस तरह के संस्थानों से निकलने वाले विद्यार्थियों को कई तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है ?

उत्तर - 69.90 प्रतिशत लोगों ने हां कहा।

19.20 प्रतिशत लोगों ने नहीं कहा।

11.00 प्रतिशत लोगों ने कहा कह नहीं सकते।

एक जायज प्रश्न: क्या हम गुलाम हैं?

मुझको ये आदेश है कि ये मेरा देश है।

भवानी प्रसाद मिश्रा

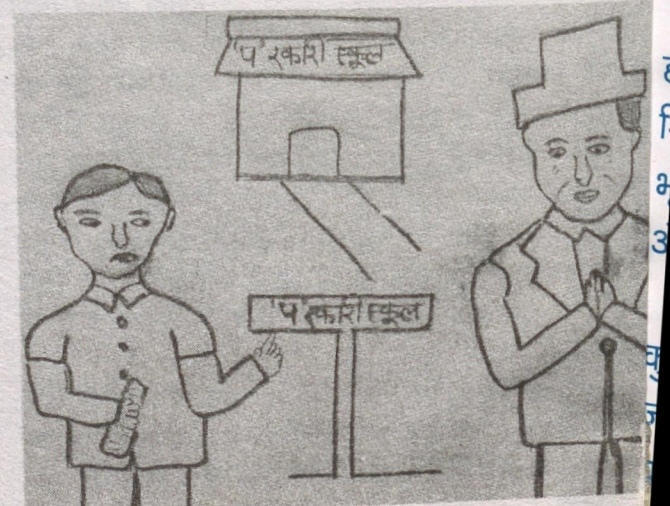
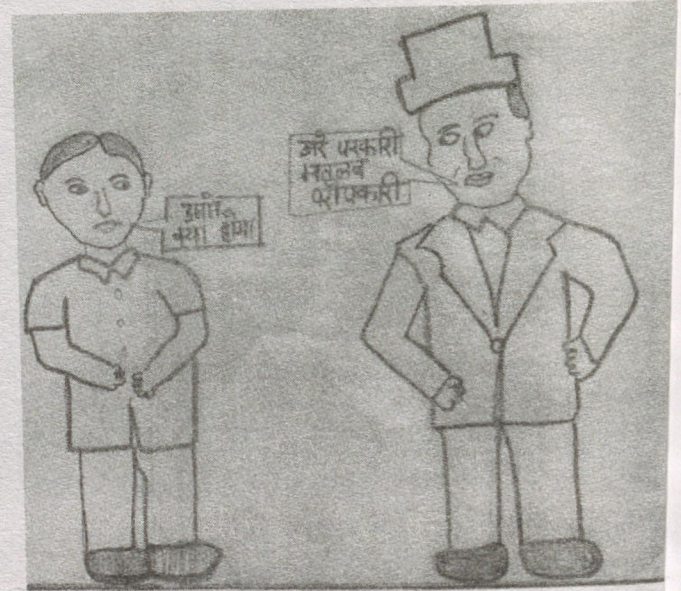
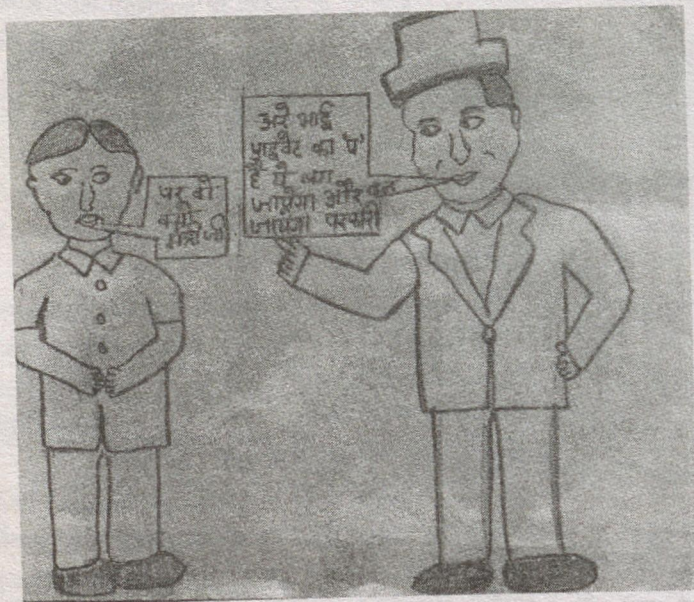
साथियों, एक सुनियोजित राजनीतिक ढांचे के तहत हमने अपने शासन की बागडोर कुछ लोगों के हाथों में सौंपी थी। इस पूरे क्रम में हमारे लहजे से, हमारी जरूरतों के हिसाब से कुछ बौद्धिक लोगों, कुछ आदर्शवादी लोगों, कुछ नियम बनाने वालों एवं कुछ प्रतिनिधियों के माध्यम से एक नीति के तहत नियम-कानून बनना एवं उनका पालन होना तय हुआ था। लेकिन हम अपने निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई शिक्षा में ही देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर वर्णित लोगों ने एक गुट बनाकर मुनाफाखोरी को जनकल्याण से ज्यादा तरजीह दी।

आज फिक्की, एसोचैम, चंद बीमा संस्थायें और मुनाफाखोरी के प्रवर्तक बताते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे एवं हम इस अर्थव्यवस्था में किस तरह खपेंगे। इस पूरे गुटतंत्र की

करतूतों के जरिये एक वर्ग को हाशिए पर ढकेला गया और एक को मुनाफे की चक्की में पीसा गया। हमारी स्वतंत्रता के विचार के खुले तौर पर परखच्चे उड़ाये गये। विश्वबैंक जैसी संस्थाओं की धुन पर हमारे तरीकों, हमारे लहजे एवं हमारी जरूरत की तरजीह को नीतियों से खदेड़ा गया। साथ ही लगातार देश का हवाला देकर यह बताया गया कि ये देश हित में और इसलिये नागरिकों के हित में भी।

भवानी प्रसाद मिश्रा की ऊपर लिखी पंक्तियों पर विचार करते हुये जरा इस जायज प्रश्न पर विचार करें। क्या हम गुलाम लोग हैं? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में तो यही दिखता है। हमें दूसरी भाषा के ज्ञान के नाम पर महज कॉल सेंटर में बोली जाने वाली अंग्रेजी की खुराक दी जाती है। विश्व बैंक के साहूकारी कदमों को हमें कल्याणकारी चश्मे से देखने की सलाह दी जाती है। जरा सोचें; क्यों हमारी विचार शक्ति को कुछ निश्चित खांचों में डालकर, हमें सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है?

आईना: सोनम झा



इस
को
स्कू
अस
इस
नयी
साम
स्तर
वृद्धि
में मा
हाल
स्तर
संभाव
सकारा
मिलती
(राष्ट्रीय
नजरिया
विश्व बैं
सुझायी
1) सार्व
2) नवाच
के मॉडल
3) दो शि
जाये।
4) मल्टीग्रे
5) आंतरि
के लिये क
शिक्षा में स
रहा है।)
6) पाठ्यक्रम
नयी तरह स
7) भारत में
विद्यालय औ
सार्वजनिक
जरूरत है।
8) मांग पक्ष
जाये।
सवाल उठते
साफ जाहिर
की शिक्षा में अ
बहुत गहरी सा
बैंक ने प्राथमिक
का नहीं छोड़ा
मसलन जिला

गरीबों का गांव और शिक्षा

'शहर से दूर
एक गरीबों का गांव रहता है
कोई सुनता नहीं
मगर वह कहता है -

हमारे यहां गरीबी है, अशिक्षा है
इसलिए नहीं कि यह हमारी इच्छा है
बल्कि मजबूरी है
क्योंकि सरकार की
गांव से बहुत दूरी है

और इसलिए सरकारी किताब
राह में लुट जाती है
मिड - डे - मील
प्रधान की गाय खाती है!

हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं
शिक्षक की गाय चराते हैं
भूख लगने पर घास खाते हैं
और घर लौट आते हैं

कुछ ऐसे भी हैं
जो ढाबे में प्लेट धोते हैं
गा चाय देते हैं

गालियां लेते हैं

ऐसा नहीं कि हमारे गांव में
लोग पढ़ना नहीं चाहते
चाहते हैं

मगर शिक्षा नहीं, जरूरी जीना है
इसलिए अशिक्षा का जहर
हमें हंसकर पीना है!

हम अंगूठा लगाने वालों की
शहरी सरकार से
बस इतनी दरखास्त है
हम पर भी ध्यान दे
जरा सम्मान दे!

शिवेन्द्र

बच्चों के बारे में

बच्चों के बारे में
बनाई गई ढेर सारी योजनाएं
ढेर सारी कविताएं
लिखी गई बच्चों के बारे में
बच्चों के लिए खोले गए
ढेर सारे स्कूल ढेर सारी किताबें
बांटी गई बच्चों के लिए
बच्चे बड़े हुए
जहां थे
वहां उठ खड़े हुए बच्चे
बच्चों में से कुछ बच्चे
हुए बनिया हाकिम
और दलाल
हुए मालामाल और खुशहाल
बाकी बच्चों ने
सड़क पर कंकड़ कूटा
दुकानों में प्यालियां धोई
साफ किया टट्टीघर
खाए तमाचे
बाजार में बिके कौड़ियों के मोल
गटर में गिर पड़े
बच्चों में से कुछ बच्चों ने
आगे चलकर
फिर बनाई योजनाएं
बच्चों के बारे में कविताएं लिखीं
स्कूल खोले
किताबें बांटी
बच्चों के लिए।

गोरख पाण्डेय